



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 14—अप्रैल 20, 2018 (चैत्र 24, 1940)  
No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 14—APRIL 20, 2018 (CHAITRA 24, 1940)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## विषय-सूची

पृष्ठ सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	195	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	185	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	9	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... *
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	297	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... 705
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस..... *
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... *
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं..... 1813
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 737
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण..... *

\*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

## CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	195	by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	185	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	9	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .....	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .....	297	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .....	705
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .....	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .....	1813
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .....	737
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi .....	*

\*Folios not received.

**भाग I—खण्ड 1****[PART I—SECTION 1]**

**[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]**

**[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]**

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2018

संख्या 11034/48/2014-रा.भा. (नीति).—राजभाषा विभाग द्वारा दिये जा रहे राजभाषा पुरस्कारों के अंतर्गत वर्ष 2018-19 से निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं :

(क) राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के लिए प्रदान की जाने वाली भीलडों के लिए मंत्रालय/विभाग/उपक्रम/बोर्ड/स्वायत्त निकाय/बैंक आदि के कार्मिकों की संख्या कम से कम 30 होने पर ही पुरस्कार के लिए विचार किया जाएगा।

(ख) कार्यालय ज्ञापन सं. 11034/48/2014-रा.भा. (नीति) दिनांक 25.03.2015 जो राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना से संबंधित है :

i. मद सं. 'क(4)' के अंतर्गत दिये जाने वाले 10 प्रोत्साहन पुरस्कार और मद सं. 'ख' के अंतर्गत दिये जाने वाला 1 प्रोत्साहन पुरस्कार वर्ष 2017 से समाप्त कर दिये गये हैं।

ii. मद सं. 'ख-(5): प्रविष्टि भेजने की विधि' के अंतर्गत निम्न उप-पद सं. (v) जोड़ दी गई है "सेवानिवृत्त कार्मिक अपनी पुस्तक, पीपीओ की कॉपी संलग्न कर, राजभाषा विभाग को सीधे भेज सकते हैं।"

iii. मद सं. 'क-(6)' और 'ख-(4)' जो सामान्य भातों के संदर्भ में हैं के अंतर्गत निम्न उप-पद सं. (xi) जोड़ दी गई है "पुरस्कार योजना के अंतर्गत केवल ISBN वाली पुस्तकों को ही भागिल किया जाएगा।"

(ग) राजभाषा कीर्ति/क्षेत्रीय पुरस्कार के लिए 60 प्रतिभात से कम अंक पाने वाले को पुरस्कार की श्रेणी में भागिल नहीं किया जाएगा।

डॉ. बिपिन बिहारी, संयुक्त सचिव

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2018

संख्या 8-65/2017-पीपी-II.— भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 26.11.1993 की अधिसूचना सं. 8-97/91-पीपी-I में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्वारा साधारण सूचना हेतु अधिसूचित किया जाता है कि संगत शीर्ष के तहत निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़कर या बदलकर शामिल की जाएंगी जिसमें उन अधिकारियों को पदनाम से विनिर्दिष्ट किया जाएगा जो अन्य देशों को निर्यात की जाने वाली वनस्पति और वनस्पति सामग्री के निरीक्षण, प्रधूमन या विसंक्रमित करने और उन देशों को निर्यात हेतु अपेक्षित पादपस्वच्छता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए प्राधिकृत हैं:

I. केन्द्र सरकार

(ixvii) प्रभारी अधिकारी

वनस्पति संगरोध केन्द्र,

मदुरै हवाई अड्डा (तमिलनाडु),

[कोड सं. 'सी' (पीपीक्यूएस) 1 (67)]

## II. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

### गुजरात

(v) कृषि उपनिदेशक (वनस्पति संगरोध),

सूरत,

(गुजरात)

{कोड सं. 'एस' (गुज.) 5}

### महाराष्ट्र

(xii) कृषि उपनिदेशक,

ठाणे,

(महाराष्ट्र)

{कोड सं. 'एस' (महा.) 12}

(xiii) कृषि उपनिदेशक,

अहमदनगर,

(महाराष्ट्र)

{कोड सं. 'एस' (महा.) 13}

(xiv) कृषि उपनिदेशक,

सतारा,

(महाराष्ट्र)

{कोड सं. 'एस' (महा.) 14}

(xv) कृषि उपनिदेशक,

लातूर,

(महाराष्ट्र)

{कोड सं. 'एस' (महा.) 15}

(xvi) कृषि उपनिदेशक,

जालना,

(महाराष्ट्र)

{कोड सं. 'एस' (महा.) 16}

डॉ. बी. राजेन्द्र  
संयुक्त सचिव

नोट: मूल अधिसूचना कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की दिनांक 26.11.1993 की अधिसूचना सं. 8-97/91-पीपी-I द्वारा जारी की गई थी और तत्पश्चात दिनांक 25.11.97 की अधिसूचना सं. 8-97/91-पीपी-I, दिनांक 30.09.1999 की अधिसूचना सं. 8-70/98-पीपी-I, दिनांक 06.11.2001 की अधिसूचना सं. 8-86/2000-पीपी-I, दिनांक 06.05.2002 की अधिसूचना सं. 8-86/2000-पीपी-I, दिनांक 30.05.2002 की अधिसूचना सं. 8-86/2000-पीपी-I, दिनांक 07.06.2004 की अधिसूचना सं. 8-33/2003-पीपी-I, दिनांक 11.05.2005 की अधिसूचना सं. 8-217/2004-पीपी-I (पार्ट), दिनांक 20.06.2005 की अधिसूचना सं. 8-217/2004-पीपी-I (पार्ट), दिनांक 08.12.2005 की अधिसूचना सं. 8-217/2004-पीपी-I (पार्ट), दिनांक 09.01.2006 की अधिसूचना सं. 8-217/2004-पीपी-I (पार्ट), दिनांक 26.12.2011 की अधिसूचना सं. 8-217/2004-पीपी-I (पार्ट), दिनांक 30.01.2013 की अधिसूचना सं. 8-217/2004-पीपी-I (पार्ट), दिनांक 06.07.2015 की अधिसूचना सं. 8-217/2004-पीपी-I (पार्ट), दिनांक 21.06.2016 की अधिसूचना सं. 8-217/2004-पीपी-I (पार्ट), दिनांक 12.01.2017 की अधिसूचना सं. 8-217/2004-पीपी-I (पार्ट) और दिनांक 13.04.2017 की अधिसूचना सं.-8-65/2017-पीपी-II द्वारा संशोधित की गई थी।

### वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट प्रभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2018

एफ. संख्या. 5(1)-बी(पी.डी.)/2018.—आम जानकारी के लिए यह घोषित किया जाता है कि वर्ष 2018-2019 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 1 अप्रैल, 2018 से 30 जून, 2018 तक 7.6% (सात दशमलव छः प्रतिशत) होगी। यह दर 1 अप्रैल, 2018 से लागू होगी। संबंधित निधियां निम्नलिखित हैं:—

1. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं)।
2. अंशदायी भविष्य निधि (भारत)।
3. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि।
4. राज्य रेलवे भविष्य निधि।
5. सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं)।
6. भारतीय आयुध विभाग भविष्य निधि।
7. भारतीय आयुध कारखाना कामगार भविष्य निधि।
8. भारतीय नौसेना गोदी कामगार भविष्य निधि।
9. रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि।
10. सशस्त्र सेना कार्मिक भविष्य निधि।

2. आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अंजना वशिष्ठ

उप-सचिव (बजट)

## मानव संसाधन विकास मंत्रालय

## (उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2017

फा.सं.9-14/2011-यू.3 (ए).—जबकि, केंद्रीय सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी के परामर्श से, उच्चतर शिक्षा संस्थान को सम विश्वविद्यालय घोषित करने के लिए सशक्तिकरण किया गया है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत कलिंगा सामाजिक विज्ञान संस्थान (केआईएसएस), भुवनेश्वर, ओडिशा को सम विश्वविद्यालय का दर्जा (नये वर्ग के तहत) प्रदान करने के लिए वर्ष 2011 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

3. और जबकि यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2010 के अनुसार आवेदन जांच और परामर्श के लिए यूजीसी को अग्रेषित किया गया था। इसी बीच, यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2010 के अतिक्रमण में नया विनियम अर्थात् यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2016 लागू किया गया है।

4. और इसके अतिरिक्त जबकि, यूजीसी के परामर्श के अनुसार, यूजीसी विनियम, 2016 के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय को संस्थान द्वारा एक अनुपूरक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अनुपूरक आवेदन को जांच और परामर्श के लिए यूजीसी को भी अग्रेषित किया गया था।

5. और जबकि, यूजीसी द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन यह सिफारिश देने हेतु कि क्या कलिंगा सामाजिक विज्ञान संस्थान (केआईएसएस), भुवनेश्वर एक ऐसा संस्थान है जो विशेष रूप से शिक्षण और अनुसंधान पर मौजूदा संस्थानों द्वारा न पढ़ाए जाने वाले 'ज्ञान के उदीयमान क्षेत्रों' पर फोकस करता है और इसके प्रस्ताव पर नए वर्ग के तहत विचार किया जा सकता है। समिति ने सर्वसम्मति से सिफारिश की कि कलिंगा सामाजिक विज्ञान संस्थान (केआईएसएस), भुवनेश्वर के सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के प्रस्ताव पर नए वर्ग के तहत विचार किया जा सकता है।

6. और इसके अलावा जबकि, जैसा 'यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2016 के तहत अपेक्षित है, यूजीसी ने संस्थान में उपलब्ध अवसंरचना और अन्य सुविधाओं के सत्यापन हेतु और ऑन साइट निरीक्षण के लिए एक अन्य विशेषज्ञ समिति गठित की।

7. और जबकि, यूजीसी विजिटिंग समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया था और यूजीसी द्वारा दिनांक 28 मार्च, 2017 को आयोजित इसकी 522वीं बैठक (मद सं. 2.04) में अनुमोदित की गई।

8. और इसके अलावा जबकि, यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और संस्थान के स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय के अपने दिनांक 19 जुलाई, 2017 के पत्र सं. 9-14/2011-यू.3(ए) द्वारा प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के साथ सैद्धांतिक रूप से सहमति दी:

- i. संस्थान, केआईएसएस द्वारा संचालित स्कूल से प्रस्तावित सम विश्वविद्यालय संस्थान के हटाए जाने के संबंध में दस्तावेजी प्रभाव प्रस्तुत करेगा।
- ii. संस्थान, यूजीसी मानदंडों के अनुसार सात प्रस्तावित विभागों के लिए अपेक्षित सदस्य संकायों की नियुक्ति करेगा।
- iii. संस्थान, प्रस्तावित केआईएसएस समविश्वविद्यालय संस्थान के नाम पर कुल आवंटित भूमि का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा क्योंकि केआईएसएस द्वारा प्रस्तुत की गई भूमि का पूर्व ब्यौरा यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में दी गई भूमि के ब्यौरे से भिन्न है।
- iv. संस्थान, यह स्पष्ट करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि क्या यह इसके द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

9. और जबकि, संस्थान ने उक्त शर्तों को पूरी करने के लिए अपनी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके अलावा, यूजीसी को अनुपालन रिपोर्ट की जांच करने और यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया कि क्या कलिंगा सामाजिक विज्ञान संस्थान (केआईएसएस), भुवनेश्वर ने नए वर्ग के तहत सम विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचना हेतु, सभी शर्तें पूरी करता है। यूजीसी ने अपने दिनांक 2 अगस्त, 2017 के पत्र सं. 35-1/2011 (सीपीपी-1/डीयू) द्वारा यह स्पष्ट किया कि संस्थान ने इस मंत्रालय के दिनांक 19 जुलाई, 2017 के पत्र सं. 9-14/2011-यू.3(ए) में उल्लिखित सभी शर्तें पूरी करते हैं।

10. अतः अब, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, यूजीसी के परामर्श पर, एतद्वारा यह घोषणा करता है कि कलिंगा सामाजिक विज्ञान संस्थान (केआईएसएस), भुवनेश्वर, ओडिशा, को नए वर्ग के तहत पांच वर्षों की अनंतिम अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ सम विश्वविद्यालय संस्थान माना जाएगा। सम विश्वविद्यालय के दर्जे की यूजीसी विशेषज्ञ समिति की पांच वर्षों की समीक्षा रिपोर्ट और आयोग की सिफारिश के आधार पर पुष्टि की जाएगी। कलिंगा सामाजिक विज्ञान संस्थान (केआईएसएस), भुवनेश्वर, ओडिशा को सम विश्वविद्यालय का दर्जा निम्नलिखित सात विभागों के लिए प्रदान किया जा रहा है:

- i. जनजातीय संस्कृति, दर्शन और पारिस्थितिकी-आध्यात्मिकता विभाग
- ii. स्वदेशी ज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- iii. तुलनात्मक जनजातीय भाषा विज्ञान और साहित्य विभाग
- iv. जनजातीय विरासत और जनजातीय भारतीय विद्या विभाग
- v. तुलनात्मक इंडिक अध्ययन और जनजातीय विज्ञान विभाग
- vi. जनजातीय संसाधन प्रबंधन विभाग
- vii. जनजातीय विधिक अध्ययन और जनजातीय अधिकार विभाग

11. उक्त पैरा 10 में की गई घोषणा इसके अलावा इस अधिसूचना के पृष्ठांकन की क्रम सं. 5 में उल्लेखित शर्तों को पूरी करने के अध्यधीन होगी।

ईशिता राय

संयुक्त सचिव

सं. एफ. 10-2/2017- यू.3 (ए).—जबकि, केंद्रीय सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी के परामर्श से, उच्चतर शिक्षा संस्थान को सम विश्वविद्यालय घोषित करने के लिए सशक्तिकरण किया गया है।

2. और जबकि, यूजीसी के परामर्श पर, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान (टीआईएफआर), मुंबई, महाराष्ट्र को निम्नलिखित मल्टी कैंपसों के साथ-साथ इस मंत्रालय की दिनांक 07.05.2002 की अधिसूचना सं. 9-48/2001-यू-3 के जरिए सम विश्वविद्यालय संस्था घोषित किया गया था:-

- (i) राष्ट्रीय रेडियो भौतिकी केन्द्र, पुणे
- (ii) राष्ट्रीय जीव विज्ञान केन्द्र, बेंगलौर
- (iii) होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केन्द्र, मुंबई

3. और जबकि, सम विश्वविद्यालय संस्था ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को दिनांक 09.02.2017 को टीआईएफआर, हैदराबाद के भाग के रूप में टीआईएफआर अंतरविषयी विज्ञान (टीसीआईएस) केन्द्र हैदराबाद में एक ऑफ-कैम्पस की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

4. और इसके अतिरिक्त जबकि, प्रस्ताव की विशेषज्ञ समिति की सहायता से यूजीसी द्वारा यूजीसी के (समवत विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2016 के प्रावधानों के संबंध में जांच की गई है। आयोग द्वारा 7 जून, 2017 को आयोजित अपनी 523वीं बैठक में (मद सं.2.06) यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट अनुमोदित की गई थी।

5. अतः, अब, यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के परामर्श से टाटा मूलभूत अनुसंधान (टीआईएफआर), मुंबई, महाराष्ट्र को टीआईएफआर, हैदराबाद में भाग के रूप में टीआईएफआर अंतर-विषयी विज्ञान केन्द्र (टीआईसीएस) के साथ भावी प्रभाव से हैदराबाद में ऑफ-कैम्पस केन्द्र शुरू करने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान किया है।

6. उपर्युक्त पैरा 5 में की गई उद्घोषणा इस अधिसूचना के पृष्ठांकन के क्रम संख्या 5 पर उल्लिखित शर्तों और यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2016 एवं समय-समय पर इसके संशोधनों, यदि कोई हो, पूरा करने के अध्यधीन होगा।

ईशिता राय

संयुक्त सचिव

#### यू.3(ए) अनुभाग

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2018

सं.एफ. 9-37/2007-यू.3(ए).—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 29.02.2008 की अधिसूचना सं. 9-37/2007-यू.3(ए) के जरिए श्री बी.एम. पाटिल मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, बीजापुर, कर्नाटक को 'बीएलडीई विश्वविद्यालय' के नाम और रीति में अपने संबंधन विश्वविद्यालय अर्थात् राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक, बेंगलूर से सम्बद्धता समाप्त होने की तारीख से पांच वर्षों की अनंतिम अवधि के लिए 'समविश्वविद्यालय' घोषित किया था। यह इस शर्त के अध्यधीन था कि यूजीसी की विशेषज्ञ समीक्षा समिति की निरीक्षण और मूल्यांकन रिपोर्ट एवं यूजीसी की तत्संबंधी सिफारिशों के आधार पर पांच वर्ष की अवधि के बाद समविश्वविद्यालय के दर्जे की पुष्टि की जाएगी।

3. और जबकि, यूजीसी इस मंत्रालय की दिनांक 29.02.2008 की अधिसूचना द्वारा यथा अपेक्षित बीएलडीई विश्वविद्यालय (समविश्वविद्यालय) के कार्यकरण की समीक्षा करने की प्रक्रिया में है।

4. और इसके अतिरिक्त जबकि, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड बनाम रबिंशंकर पात्रो एवं अन्य द्वारा दायर सिविल अपील सं. 17869-17870/2017 (एसएलपी (सी) सं. 19807-19808/2012 से उत्पन्न) और विजय कुमार एवं अन्य बनाम करतार सिंह एवं अन्य शीर्षक सिविल अपील सं. 17902-17905/2017 (एसएलपी सी सं. 35793-96/2012 से उत्पन्न) में अपने दिनांक 03.11.2017 के आदेश में यह निर्णय दिया है कि यूजीसी, आज से एक माह के भीतर यूजीसी अधिनियम की धारा 23 के कार्यान्वयन और समविश्वविद्यालयों को 'विश्वविद्यालय' शब्द का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के समुचित उपाय करेगा।

5. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 23 में प्रावधान है 'किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के द्वारा अथवा उसके तहत स्थापित या समाविष्ट विश्वविद्यालय से इतर कोई भी संस्था, चाहे कॉर्पोरेट निकाय हो या नहीं, किसी भी तरह से, चाहे जो हो, अपने नाम के साथ 'विश्वविद्यालय' शब्द जोड़ने की पात्र नहीं होगी; परंतु इस धारा में दिया गया कुछ भी इस अधिनियम के प्रवर्तन से दो वर्ष की अवधि के लिए ऐसी संस्था पर लागू नहीं होगा, जिसके नाम के साथ 'विश्वविद्यालय' शब्द इसके प्रवर्तन से ठीक पूर्व जुड़ा था।'

6. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुसार और यूजीसी के परामर्श से एतद्वारा यह अधिसूचना जारी कर 'बीएलडीई विश्वविद्यालय' के नाम से 'विश्वविद्यालय' शब्द का विलोपन करके इसका नाम बदलकर 'बीएलडीई' करती है। 'बीएलडीई', अपने नाम में 'विश्वविद्यालय' प्रत्यय शब्द का उपयोग नहीं करेगा लेकिन इसके आगे कोष्ठक के भीतर 'समविश्वविद्यालय' प्रत्यय शब्द का उल्लेख कर सकता है।

7. बीएलडीई दिनांक 29.02.2008 की पूर्व अधिसूचना में उल्लिखित अन्य शर्तों का पालन करता रहेगा।

संजय कुमार सिन्हा

संयुक्त सचिव



सं.एफ. 9-34/2007-यू.3(ए).—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 22.07.2008 की अधिसूचना सं. 9-34/2007-यू.3(ए) के जरिए “क्राईस्ट कॉलेज (स्वायत्त), बंगलौर, कर्नाटक, को इसके संबद्धता कॉलेज अर्थात् बंगलौर विश्वविद्यालय से सम्बद्धता समाप्त होने की तारीख से पांच वर्षों की अनंतिम अवधि के लिए “क्राईस्ट विश्वविद्यालय” घोषित किया था। यह इस शर्त के अधीन था कि यूजीसी की विशेषज्ञ समीक्षा समिति की निरीक्षण और मूल्यांकन रिपोर्ट एवं यूजीसी की तत्संबंधी सिफारिशों के आधार पर पांच वर्ष की अवधि के बाद समविश्वविद्यालय के दर्जा की पुष्टि की जाएगी।

3. और जबकि, यूजीसी इस मंत्रालय की दिनांक 22.07.2008 की अधिसूचना द्वारा यथा अपेक्षित क्राईस्ट विश्वविद्यालय (समविश्वविद्यालय), बंगलौर, कर्नाटक की कार्यपद्धति की समीक्षा करने की प्रक्रिया में है।

4. और इसके अतिरिक्त जबकि, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड बनाम रवि शंकर पात्रो एवं अन्य द्वारा दायर सिविल अपील सं. 17869-17870/2017 (एसएलपी (सी) सं. 19807-19808/2012 से उत्पन्न) और विजय कुमार एवं अन्य बनाम करतार सिंह एवं अन्य शीर्षक सिविल अपील सं. 17902-17905/2017 (एसएलपी सी सं. 35793-96/2012 से उत्पन्न) में अपने दिनांक 03.11.2017 के आदेश में यह निर्णय दिया था कि यूजीसी, आज से एक माह के भीतर यूजीसी अधिनियम की धारा 23 के कार्यान्वयन और समविश्वविद्यालयों को “विश्वविद्यालय” शब्द का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के समुचित उपाय करेगा।

5. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 23 में प्रावधान है “किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के द्वारा अथवा उसके तहत स्थापित या समाविष्ट विश्वविद्यालय से इतर कोई भी संस्था, चाहे कॉर्पोरेट निकाय हो या नहीं, किसी भी तरह से, चाहे जो हो, अपने नाम के साथ “विश्वविद्यालय” शब्द जोड़ने की पात्र नहीं होगी; परंतु इस धारा में दिया गया कुछ भी इस अधिनियम के प्रवर्तन से दो वर्ष की अवधि के लिए ऐसी संस्था पर लागू नहीं होगा, जिसके नाम के साथ “विश्वविद्यालय” शब्द इसके प्रवर्तन से ठीक पूर्व जुड़ा था।”

6. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार और यूजीसी के परामर्श से एतद्वारा यह अधिसूचना जारी करके “क्राईस्ट विश्वविद्यालय” के नाम से “विश्वविद्यालय” शब्द का विलोपन करके इसका नाम बदलकर “क्राईस्ट” करती है। “क्राईस्ट”, अपने नाम में “विश्वविद्यालय” प्रत्यय शब्द का उपयोग नहीं करेगा लेकिन इसके आगे कोष्ठकों के भीतर “समविश्वविद्यालय” प्रत्यय शब्द का उल्लेख कर सकता है।

7. “क्राईस्ट” दिनांक 22.07.2008 की पूर्व अधिसूचना में उल्लिखित अन्य शर्तों का पालन करता रहेगा।

संजय कुमार सिन्हा

संयुक्त सचिव

सं.एफ. 9-48/2007-यू.3(ए).—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 14.08.2008 की अधिसूचना सं. 9-48/2007-यू.3(ए) के जरिए “ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय”, देहरादून, उत्तराखंड जिसमें ग्राफिक एरा प्रौद्योगिकी संस्थान शामिल है, को इसके संबद्ध विश्वविद्यालय अर्थात् उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय और हेमवतीनंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से सम्बद्धता समाप्त होने की तारीख से पांच वर्षों की अनंतिम अवधि के लिए “समविश्वविद्यालय” घोषित किया था। यह इस शर्त के अधीन था कि यूजीसी की विशेषज्ञ समीक्षा समिति की निरीक्षण और मूल्यांकन रिपोर्ट एवं यूजीसी की तत्संबंधी सिफारिशों के आधार पर पांच वर्ष की अवधि के बाद समविश्वविद्यालय के दर्जे की पुष्टि की जाएगी।

3. और जबकि, यूजीसी इस मंत्रालय की दिनांक 14.08.2008 की यथा अपेक्षित अधिसूचना द्वारा “ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय”, देहरादून, उत्तराखंड (समविश्वविद्यालय) की कार्यपद्धति की समीक्षा करने की प्रक्रिया में है।

4. और इसके अतिरिक्त जबकि, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड बनाम रबिंशंकर पात्रो एवं अन्य द्वारा दायर सिविल अपील सं. 17869-17870/2017 (एसएलपी (सी) सं. 19807-19808/2012 से उत्पन्न) और विजय कुमार एवं अन्य बनाम करतार सिंह एवं अन्य शीर्षक सिविल अपील सं. 17902-17905/2017 (एसएलपी सी सं. 35793-96/2012 से उत्पन्न) में अपने दिनांक 03.11.2017 के आदेश में यह निर्णय दिया था कि यूजीसी, आज से एक माह के भीतर यूजीसी अधिनियम की धारा 23 के कार्यान्वयन और समविश्वविद्यालयों को “विश्वविद्यालय” शब्द का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के समुचित उपाय करेगा।

5. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 23 में प्रावधान है “किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के द्वारा अथवा उसके तहत स्थापित या समाविष्ट विश्वविद्यालय से इतर कोई भी संस्था, चाहे कॉर्पोरेट निकाय हो या नहीं, किसी भी तरह से, चाहे जो हो, अपने नाम के साथ “विश्वविद्यालय” शब्द जोड़ने की पात्र नहीं होगी: परंतु इस धारा में दिया गया कुछ भी इस अधिनियम के प्रवर्तन से दो वर्ष की अवधि के लिए ऐसी संस्था पर लागू नहीं होगा, जिसके नाम के साथ “विश्वविद्यालय” शब्द इसके प्रवर्तन से ठीक पूर्व जुड़ा था।”

6. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश के अनुसार और यूजीसी की सलाह पर एतदद्वारा यह अधिसूचना जारी कर “विश्वविद्यालय” शब्द का विलोपन करके “ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय” के नाम को बदलकर “ग्राफिक एरा” करती है। “ग्राफिक एरा”, अपने नाम में “विश्वविद्यालय” प्रत्यय शब्द का उपयोग नहीं करेगा लेकिन इसके आगे कोष्ठकों के भीतर “समविश्वविद्यालय” प्रत्यय शब्द का उल्लेख कर सकता है।

7. “ग्राफिक एरा” दिनांक 14.08.2008 की पूर्व अधिसूचना में उल्लिखित अन्य शर्तों का पालन करता रहेगा।

संजय कुमार सिन्हा

संयुक्त सचिव

सं.एफ. 10-17/62-यू.2/यू.3(ए) पार्ट-1. जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 19.06.1962 की अधिसूचना सं. 10-17/62-यू.2 के तहत “गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय”, हरिद्वार को समविश्वविद्यालय घोषित किया था।

3. और आगे जबकि, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड बनाम रबिंशंकर पात्रो एवं अन्य द्वारा दायर सिविल अपील सं. 17869-17870/2017 (एसएलपी (सी) सं. 19807-19808/2012 से उत्पन्न) और विजय कुमार एवं अन्य बनाम करतार सिंह एवं अन्य नामक सिविल अपील सं. 17902-17905/2017 (एसएलपी सी सं. 35793-96/2012 से उत्पन्न) में अपने दिनांक 03.11.2017 के आदेश में यह निर्णय दिया था कि यूजीसी, आज से एक माह के भीतर यूजीसी अधिनियम की धारा 23 के कार्यान्वयन और समविश्वविद्यालयों को “विश्वविद्यालय” शब्द का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के समुचित उपाय करेगा।

4. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 23 में प्रावधान है “किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के द्वारा अथवा उसके तहत स्थापित या समाविष्ट विश्वविद्यालय से इतर कोई भी संस्था, चाहे कॉर्पोरेट निकाय हो या नहीं, किसी भी ढंग से, जो भी हो, अपने नाम के साथ “विश्वविद्यालय” शब्द जोड़ने की पात्र नहीं होगी: परंतु इस धारा में दिया गया कुछ भी इस अधिनियम के प्रवर्तन से दो वर्ष की अवधि के लिए ऐसी संस्था पर लागू नहीं होगा, जिसके नाम के साथ “विश्वविद्यालय” शब्द इसके प्रवर्तन से ठीक पूर्व जुड़ा था।”

5. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार और यूजीसी की सलाह पर एतदद्वारा यह अधिसूचना जारी करके इसके नाम से “विश्वविद्यालय” शब्द को “विद्यापीठ” शब्द से प्रतिस्थापित कर इसका नाम “गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय” से बदलकर “गुरुकुल कांगड़ी

विद्यापीठ' करती है। 'गुरुकुल कांगड़ी विद्यापीठ' अपने नाम में 'विश्वविद्यालय' प्रत्यय शब्द का उपयोग नहीं करेगी लेकिन इसके आगे कोष्ठकों के भीतर 'समविश्वविद्यालय' शब्द का उल्लेख कर सकती है।

संजय कुमार सिन्हा

संयुक्त सचिव

सं.एफ. 9-57/2007-यू.3(ए) जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 19.12.2008 की अधिसूचना सं. 9-57/2007-यू.3(ए) के जरिए श्री भगवान महावीर जैन कॉलेज, बंगलौर, कर्नाटक को इसके संबद्ध विश्वविद्यालय अर्थात् बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर से सम्बद्धता समाप्त होने की तारीख से पांच वर्षों की अनंतिम अवधि के लिए 'जैन विश्वविद्यालय के नाम और शैली में समविश्वविद्यालय' घोषित किया था। यह इस शर्त के अधीन था कि यूजीसी की विशेषज्ञ समीक्षा समिति की निरीक्षण और मूल्यांकन रिपोर्ट एवं यूजीसी की तत्संबंधी सिफारिशों के आधार पर 5 वर्ष की अवधि के बाद समविश्वविद्यालय के दर्जे की पुष्टि की जाएगी।

3. और जबकि, यूजीसी इस मंत्रालय की दिनांक 19.12.2008 की अधिसूचना द्वारा यथा अपेक्षित जैन विश्वविद्यालय (समविश्वविद्यालय), बंगलौर, कर्नाटक की कार्यपद्धति की समीक्षा करने की प्रक्रिया में है।

4. और इसके अतिरिक्त जबकि, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम रबिंशंकर पात्रो एवं अन्य द्वारा दायर सिविल अपील सं. 17869-17870/2017 (एसएलपी (सी) सं. 19807-19808/2012 से उत्पन्न) और विजय कुमार एवं अन्य बनाम करतार सिंह एवं अन्य शीर्षक सिविल अपील सं. 17902-17905/2017 (एसएलपी सी सं. 35793-96/2012 से उत्पन्न) में अपने दिनांक 03.11.2017 के आदेश में यह निर्णय दिया था कि यूजीसी, आज से एक माह के भीतर यूजीसी अधिनियम की धारा 23 के कार्यान्वयन और समविश्वविद्यालयों को 'विश्वविद्यालय' शब्द का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के समुचित उपाय करेगा।

5. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 23 में प्रावधान है 'किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के द्वारा अथवा उसके तहत स्थापित या समाविष्ट विश्वविद्यालय से इतर कोई भी संस्था, चाहे कॉर्पोरेट निकाय हो या नहीं, किसी भी तरह से, चाहे जो हो, अपने नाम के साथ 'विश्वविद्यालय' शब्द जोड़ने की पात्र नहीं होगी; परंतु इस धारा में दिया गया कुछ भी इस अधिनियम के प्रवर्तन से दो वर्ष की अवधि के लिए ऐसी संस्था पर लागू नहीं होगा, जिसके नाम के साथ 'विश्वविद्यालय' शब्द इसके प्रवर्तन से ठीक पूर्व जुड़ा था।'

6. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार और यूजीसी के परामर्श से एतद्वारा यह अधिसूचना जारी करके 'जैन विश्वविद्यालय' के नाम से 'विश्वविद्यालय' शब्द का विलोपन करके इसका नाम बदलकर 'जैन' करती है। 'जैन', अपने नाम में 'विश्वविद्यालय' प्रत्यय शब्द का उपयोग नहीं करेगा लेकिन इसके आगे कोष्ठकों के भीतर 'समविश्वविद्यालय' प्रत्यय शब्द का उल्लेख कर सकता है।

7. 'जैन' दिनांक 19.12.2008 की पूर्व अधिसूचना में उल्लिखित अन्य शर्तों का पालन करता रहेगा।

संजय कुमार सिन्हा

संयुक्त सचिव

सं.एफ. 9-9/2003-यू.3(ए).— जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 28.05.2008 की अधिसूचना सं. 9-9/2003-यू.3 के जरिए “जगतगुरु श्री शिवरथीश्वरा विश्वविद्यालय (जेएसएसयू), मैसूर, कर्नाटक”, जिसमें (i) जेएसएस मेडिकल कॉलेज, मैसूर (ii) जेएसएस इंटर कॉलेज, मैसूर, (iii) जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मसी, मैसूर और जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मसी, ऊटी (तमिलनाडु) शामिल हैं, को इसके संबद्ध विश्वविद्यालय अर्थात् राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, बंगलौर और एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी, चेन्नई, तमिलनाडु से सम्बद्धता समाप्त होने की तारीख से पांच वर्षों की अनंतिम अवधि के लिए “समविश्वविद्यालय” घोषित किया था। यह इस शर्त के अधीन था कि यूजीसी की विशेषज्ञ समीक्षा समिति की निरीक्षण और मूल्यांकन रिपोर्ट एवं यूजीसी की तत्संबंधी सिफारिशों के आधार पर पांच वर्ष की अवधि के बाद समविश्वविद्यालय के दर्जे की पुष्टि की जाएगी। यह स्पष्ट किया गया था कि जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मसी, ऊटी जेएसएसयू के ऑफ कैम्पस के रूप में कार्य करेगा।

3. और इसके अतिरिक्त जबकि, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम रबिंशंकर पात्रो एवं अन्य द्वारा दायर सिविल अपील सं. 17869-17870/2017 (एसएलपी (सी) सं. 19807-19808/2012 से उत्पन्न) और विजय कुमार एवं अन्य बनाम करतार सिंह एवं अन्य शीर्षक सिविल अपील सं. 17902-17905/2017 (एसएलपी सी सं. 35793-96/2012 से उत्पन्न) में अपने दिनांक 03.11.2017 के आदेश में यह निर्णय दिया था कि यूजीसी, आज से एक माह के भीतर यूजीसी अधिनियम की धारा 23 के कार्यान्वयन और समविश्वविद्यालयों को “विश्वविद्यालय” शब्द का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के समुचित उपाय करेगा।

4. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 23 में प्रावधान है “किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के द्वारा अथवा उसके तहत स्थापित या समाविष्ट विश्वविद्यालय से इतर कोई भी संस्था, चाहे कॉर्पोरेट निकाय हो या नहीं, किसी भी तरह से, चाहे जो हो, अपने नाम के साथ “विश्वविद्यालय” शब्द जोड़ने की पात्र नहीं होगी: परंतु इस धारा में दिया गया कुछ भी इस अधिनियम के प्रवर्तन से दो वर्ष की अवधि के लिए ऐसी संस्था पर लागू नहीं होगा, जिसके नाम के साथ “विश्वविद्यालय” शब्द इसके प्रवर्तन से ठीक पूर्व जुड़ा था।”

5. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुसार और यूजीसी की सलाह पर एतद्वारा यह अधिसूचना जारी कर “जगतगुरु श्री शिवरथीश्वरा विश्वविद्यालय (जेएसएसयू), मैसूर, कर्नाटक का नाम बदलकर “जेएसएस उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमी” करती है। “जेएसएस उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी”, अपने नाम में “विश्वविद्यालय” प्रत्यय शब्द का उपयोग नहीं करेगी लेकिन इसके आगे कोष्ठकों के भीतर “समविश्वविद्यालय” शब्द का उल्लेख कर सकती है।

6. “जेएसएस उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी” दिनांक 28.05.2008 की पूर्व अधिसूचना में उल्लिखित अन्य शर्तों का पालन करती रहेगी।

संजय कुमार सिन्हा

संयुक्त सचिव

सं.एफ. 9-23/2005-यू.3(ए).—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 05.01.2009 की अधिसूचना सं. 9-23/2005-यू.3(ए) द्वारा “लिंगाया प्रबंधन और प्रौद्योगिकी संस्थान, फरीदाबाद”, को इसके संबद्ध विश्वविद्यालय अर्थात् महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा से सम्बद्धता समाप्त होने की तारीख से पांच वर्षों की अनंतिम अवधि के लिए “लिंगाया विश्वविद्यालय” को नाम और शैली में समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया था। यह इस शर्त के अधीन था कि यूजीसी की विशेषज्ञ समीक्षा समिति की निरीक्षण और मूल्यांकन रिपोर्ट एवं यूजीसी की तत्संबंधी सिफारिशों के आधार पर पांच वर्ष की अवधि के बाद समविश्वविद्यालय के दर्जे की पुष्टि की जाएगी।

3. और जबकि, यूजीसी इस मंत्रालय की दिनांक 05.01.2009 की यथा अपेक्षित अधिसूचना द्वारा “लिंगाया विश्वविद्यालय”, फरीदाबाद (समविश्वविद्यालय) की कार्यपद्धति की समीक्षा करने की प्रक्रिया में है।

4. और आगे जबकि, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड बनाम रबिंशंकर पात्रो एवं अन्य द्वारा दायर सिविल अपील सं. 17869-17870/2017 (एसएलपी (सी) सं. 19807-19808/2012 से उत्पन्न) और विजय कुमार एवं अन्य बनाम करतार सिंह एवं अन्य शीर्षक सिविल अपील सं. 17902-17905/2017 (एसएलपी सी सं. 35793-96/2012 से उत्पन्न) में अपने दिनांक 03.11.2017 के आदेश में यह निर्णय दिया था कि यूजीसी, आज से एक माह के भीतर यूजीसी अधिनियम की धारा 23 के कार्यान्वयन और समविश्वविद्यालयों को “विश्वविद्यालय” शब्द का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के समुचित उपाय करेगा।

5. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 23 में प्रावधान है “किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के द्वारा अथवा उसके तहत स्थापित या समाविष्ट विश्वविद्यालय से इतर कोई भी संस्था, चाहे कॉर्पोरेट निकाय हो या नहीं, किसी भी तरह से, चाहे जो हो, अपने नाम के साथ “विश्वविद्यालय” शब्द जोड़ने की पात्र नहीं होगी; परंतु इस धारा में दिया गया कुछ भी इस अधिनियम के प्रवर्तन से दो वर्ष की अवधि के लिए ऐसी संस्था पर लागू नहीं होगा, जिसके नाम के साथ “विश्वविद्यालय” शब्द इसके प्रवर्तन से ठीक पूर्व जुड़ा था।”

6. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार और यूजीसी के परामर्श से एतदद्वारा यह अधिसूचना जारी करके “लिंगाया विश्वविद्यालय” फरीदाबाद, हरियाणा के नाम से “विश्वविद्यालय” शब्द को “विद्यापीठ” से बदलकर “लिंगाया विद्यापीठ” करती है। “लिंगाया विद्यापीठ”, अपने नाम में “विश्वविद्यालय” प्रत्यय शब्द का उपयोग नहीं करेगी लेकिन इसके आगे कोष्ठकों के भीतर “समविश्वविद्यालय” शब्द का उल्लेख कर सकती है।

7. “लिंगाया विद्यापीठ” दिनांक 05.01.2009 की पूर्व अधिसूचना में उल्लिखित अन्य शर्तों का पालन करती रहेगी।

संजय कुमार सिन्हा

संयुक्त सचिव

सं.एफ. 9-65/2006-यू.3(ए) जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 12.06.2007 की अधिसूचना सं. 9-65/2006-यू.3(ए) द्वारा “महर्षि मार्कण्डेय विश्वविद्यालय, मुलाना-अंबाला (हरियाणा)” जिसमें निम्नलिखित शिक्षण संस्थान शामिल हैं, को इन इसके संबद्ध विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, हरियाणा से इन संस्थानों की सम्बद्धता समाप्त होने की तारीख से समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया था।

- i. एम.एम. इंजीनियरिंग, कॉलेज, मुलाना, अंबाला;
- ii. एम.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस मैनेजमेंट (एमसीए), मुलाना, अंबाला;
- iii. एम.एम. कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड रिसर्च, मुलाना, अंबाला;
- iv. एम.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथैरेपी एंड रिहैबिलिटेशन, मुलाना, अंबाला;
- v. एम.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस मैनेजमेंट (होटल मैनेजमेंट), मुलाना, अंबाला;
- vi. एम.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, मुलाना, अंबाला;
- vii. एम.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मुलाना, अंबाला;
- viii. एम.एम. कालेज ऑफ नर्सिंग, मुलाना, अंबाला और;
- ix. एम.एम. कालेज ऑफ फार्मसी, मुलाना, अंबाला; और
- x. एम.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च नर्सिंग कॉलेज, मुलाना, अंबाला।

3. और इसके अतिरिक्त जबकि, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड बनाम रबिंशंकर पात्रो एवं अन्य द्वारा दायर सिविल अपील सं. 17869-17870/2017 (एसएलपी (सी) सं. 19807-19808/2012 से उत्पन्न) और

विजय कुमार एवं अन्य बनाम करतार सिंह एवं अन्य शीर्षक सिविल अपील सं. 17902-17905/2017 (एसएलपी सी सं. 35793-96/2012 से उत्पन्न) में अपने दिनांक 03.11.2017 के आदेश में यह निर्णय दिया था कि यूजीसी, आज से एक माह के भीतर यूजीसी अधिनियम की धारा 23 के कार्यान्वयन और समविश्वविद्यालयों को “विश्वविद्यालय” शब्द का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के समुचित उपाय करेगा।

4. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 23 में प्रावधान है “किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के द्वारा अथवा उसके तहत स्थापित या समाविष्ट विश्वविद्यालय से इतर कोई भी संस्था, चाहे कॉर्पोरेट निकाय हो या नहीं, किसी भी तरह से, चाहे जो हो, अपने नाम के साथ “विश्वविद्यालय” शब्द जोड़ने की पात्र नहीं होगी; परंतु इस धारा में दिया गया कुछ भी इस अधिनियम के प्रवर्तन से दो वर्ष की अवधि के लिए ऐसी संस्था पर लागू नहीं होगा, जिसके नाम के साथ “विश्वविद्यालय” शब्द इसके प्रवर्तन से ठीक पूर्व जुड़ा था।”

5. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार और यूजीसी के परामर्श से एतद्वारा यह अधिसूचना जारी करके “महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय” के “विश्वविद्यालय” शब्द को हटा कर उसका नाम “महर्षि मार्कंडेश्वर” करती है। “महर्षि मार्कंडेश्वर”, अपने नाम में “विश्वविद्यालय” प्रत्यय शब्द का उपयोग नहीं करेगा लेकिन इसके आगे कोष्ठकों के भीतर “समविश्वविद्यालय” प्रत्यय शब्द का उल्लेख कर सकता है।

6. “महर्षि मार्कंडेश्वर” दिनांक 12.06.2007 की पूर्व अधिसूचना में उल्लिखित अन्य शर्तों का पालन करता रहेगा।

संजय कुमार सिन्हा

संयुक्त सचिव

सं.एफ. 9-3/2007-यू.3(ए).—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 21.10.2008 की अधिसूचना सं. 9-3/2007-यू.3(ए) के तहत ‘मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, फरीदाबाद, हरियाणा, जिसमें कैरियर प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान शामिल है, को इसके संबद्ध विश्वविद्यालय अर्थात् महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा से सम्बद्धता समाप्त होने की तारीख से पांच वर्षों की अनंतिम अवधि के लिए “समविश्वविद्यालय” घोषित किया था। यह इस शर्त के अध्वधीन था कि यूजीसी की विशेषज्ञ समीक्षा समिति की निरीक्षण और मूल्यांकन रिपोर्ट एवं यूजीसी की तत्संबंधी सिफारिशों के आधार पर पांच वर्ष की अवधि के बाद समविश्वविद्यालय के दर्जे की पुष्टि की जाएगी।

3. और जबकि, यूजीसी मंत्रालय की दिनांक 21.10.2008 की अधिसूचना द्वारा यथा अपेक्षित मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (समविश्वविद्यालय), फरीदाबाद की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने की प्रक्रिया में है।

4. और इसके अतिरिक्त जबकि, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड बनाम रबिंशंकर पात्रो एवं अन्य द्वारा दायर सिविल अपील सं. 17869-17870/2017 (एसएलपी (सी) सं. 19807-19808/2012 से उत्पन्न) और विजय कुमार एवं अन्य बनाम करतार सिंह एवं अन्य नामक सिविल अपील सं. 17902-17905/2017 (एसएलपी (सी) सं. 35793-96/2012 से उत्पन्न) में अपने दिनांक 03.11.2017 के आदेश में यह निर्णय दिया था कि यूजीसी, आज से एक माह के भीतर यूजीसी अधिनियम की धारा 23 के कार्यान्वयन और समविश्वविद्यालयों को “विश्वविद्यालय” शब्द का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के समुचित उपाय करेगा।

5. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 23 में प्रावधान है “किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के द्वारा अथवा उसके तहत स्थापित या समाविष्ट विश्वविद्यालय से इतर कोई भी संस्था, चाहे कॉर्पोरेट निकाय हो या नहीं, किसी भी ढंग से, जो भी हो, अपने नाम के साथ “विश्वविद्यालय” शब्द जोड़ने की पात्र नहीं होगी; परंतु इस धारा में दिया गया कुछ भी इस अधिनियम के प्रवर्तन से दो वर्ष की अवधि के लिए ऐसी संस्था पर लागू नहीं होगा, जिसके नाम के साथ “विश्वविद्यालय” शब्द इसके प्रवर्तन से ठीक पूर्व जुड़ा था।”

6. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार और यूजीसी की सलाह पर एतद्वारा यह अधिसूचना जारी करके “मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय

विश्वविद्यालय', फरीदाबाद, हरियाणा संस्थान की इच्छानुसार उसका नाम बदलकर 'मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और अध्ययन संस्थान' करती है। मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और अध्ययन संस्थान, अपने नाम में 'विश्वविद्यालय' प्रत्यय शब्द का उपयोग नहीं करेगा लेकिन इसके आगे कोष्ठकों के भीतर 'समविश्वविद्यालय' प्रत्यय शब्द का उल्लेख कर सकता है।

7. 'मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और अध्ययन संस्थान दिनांक 21.10.2008 की पूर्व अधिसूचना में उल्लिखित अन्य शर्तों का पालन करता रहेगा।

संजय कुमार सिन्हा

संयुक्त सचिव

सं.एफ. 9-42/2005-यू.3(ए).—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 27.06.2008 की अधिसूचना सं. 9-42/2005-यू.3(ए) के तहत 'नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय', इलाहाबाद, जिसमें राजीव गांधी स्नातकोत्तर कॉलेज शामिल है, को इसके संबद्ध विश्वविद्यालय अर्थात् चौधरी शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर से सम्बद्धता समाप्त होने की तारीख से तीन वर्षों की अनंतिम अवधि के लिए 'समविश्वविद्यालय' घोषित किया था। यह इस शर्त के अधीन था कि यूजीसी की विशेषज्ञ समीक्षा समिति की निरीक्षण और मूल्यांकन रिपोर्ट एवं यूजीसी की तत्संबंधी सिफारिशों के साथ-साथ विशेषज्ञता समिति द्वारा बताई गई इसकी मौजूदा कमियों को दूर करने के आधार पर तीन वर्ष की अवधि के बाद समविश्वविद्यालय के दर्जे की पुष्टि की जाएगी।

3. और जबकि, यूजीसी नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय (समविश्वविद्यालय) इस मंत्रालय की दिनांक 27.06.2008 की अधिसूचना द्वारा यथा अपेक्षित कार्य पद्धति की समीक्षा करने की प्रक्रिया में है।

4. और आगे जबकि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड बनाम रबिंशंकर पात्रो एवं अन्य द्वारा दायर सिविल अपील सं. 17869-17870/2017 (एसएलपी (सी) सं. 19807-19808/2012 से उत्पन्न) और विजय कुमार एवं अन्य बनाम करतार सिंह एवं अन्य नामक सिविल अपील सं. 17902-17905/2017 (एसएलपी सी सं. 35793-96/2012 से उत्पन्न) में अपने दिनांक 03.11.2017 के आदेश में यह निर्णय दिया था कि यूजीसी, आज से एक माह के भीतर यूजीसी अधिनियम की धारा 23 के कार्यान्वयन और समविश्वविद्यालयों को 'विश्वविद्यालय' शब्द का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के समुचित उपाय करेगा।

5. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 23 में प्रावधान है 'किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के द्वारा अथवा उसके तहत स्थापित या समाविष्ट विश्वविद्यालय से इतर कोई भी संस्था, चाहे कॉर्पोरेट निकाय हो या नहीं, किसी भी तरह से, चाहे जो हो, अपने नाम के साथ 'विश्वविद्यालय' शब्द जोड़ने की पात्र नहीं होगी; परंतु इस धारा में दिया गया कुछ भी इस अधिनियम के प्रवर्तन से दो वर्ष की अवधि के लिए ऐसी संस्था पर लागू नहीं होगा, जिसके नाम के साथ 'विश्वविद्यालय' शब्द इसके प्रवर्तन से ठीक पूर्व जुड़ा था।'

6. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार और यूजीसी की सलाह पर एतद्वारा यह अधिसूचना जारी करके 'नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय' के नाम से 'विश्वविद्यालय' शब्द का विलोपन करके इसका नाम बदलकर 'नेहरू ग्राम भारती' करती है। 'नेहरू ग्राम भारती', अपने नाम में 'विश्वविद्यालय' प्रत्यय शब्द का उपयोग नहीं करेगी लेकिन इसके आगे कोष्ठकों के भीतर 'समविश्वविद्यालय' शब्द का उल्लेख कर सकती है।

7. 'नेहरू ग्राम भारती' दिनांक 27.06.2008 की पूर्व अधिसूचना में उल्लिखित अन्य शर्तों का पालन करती रहेगी।

संजय कुमार सिन्हा

संयुक्त सचिव

सं.एफ. 9-13/2007-यू3(ए).—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 04.06.2008 की अधिसूचना सं. 9-13/2007-यू.3(ए) के द्वारा “निट्टे विश्वविद्यालय, मंगलौर, कर्नाटक, जिसमें ए.बी. शेटी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, देरालकट्टे, मंगलौर शामिल है, को इसके संबद्ध विश्वविद्यालय अर्थात् राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक, बंगलौर से संबद्धता समाप्त होने की तारीख से “सम-विश्वविद्यालय” घोषित किया था। यह घोषणा निम्नलिखित शर्तें पूरी करने के अध्याधीन थी:

- i. प्रवर्तक न्यास अर्थात् निट्टे शिक्षा न्यास द्वारा सृजित 5 करोड़ रूपए की कायिक निधि को 2.50 करोड़ रूपए की प्रत्येक सावधि बैंक जमा के माध्यम से “निट्टे विश्वविद्यालय न्यास” के नाम अंतर्गत और निवेशित किया जाना चाहिए। यह कायिक निधि स्वरूप में अपरिवर्तनीय होगी। सावधि जमा को बिना यूजीसी की पूर्व सहमति के परिसमाप्त नहीं किया जाना चाहिए।
- ii. संगम जापन (एमओए) और “निट्टे विश्वविद्यालय” की नियमावली यूजीसी द्वारा निर्धारित नियमावली और आदर्श संगम जापन (एमओए) के अनुरूप होनी चाहिए और इसलिए यह यूजीसी द्वारा प्रमाणित की जाती है।

3. और आगे जबकि, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड बनाम रबिंशंकर पात्रो एवं अन्य द्वारा दायर सिविल अपील सं. 17869-17870/2017 (एसएलपी (सी) सं. 19807-19808/2012 से उत्पन्न) और विजय कुमार एवं अन्य बनाम करतार सिंह एवं अन्य शीर्षक सिविल अपील सं. 17902-17905/2017 (एसएलपी सी सं. 35793-96/2012 से उत्पन्न) में अपने दिनांक 03.11.2017 के आदेश में यह निर्णय दिया था कि यूजीसी, आज से एक माह के भीतर यूजीसी अधिनियम की धारा 23 के कार्यान्वयन और समविश्वविद्यालयों को “विश्वविद्यालय” शब्द का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के समुचित उपाय करेगा।

4. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 23 में प्रावधान है “किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के द्वारा अथवा उसके तहत स्थापित या समाविष्ट विश्वविद्यालय से इतर कोई भी संस्था, चाहे कॉर्पोरेट निकाय हो या नहीं, किसी भी तरह से, चाहे जो हो, अपने नाम के साथ “विश्वविद्यालय” शब्द जोड़ने की पात्र नहीं होगी; परंतु इस धारा में दिया गया कुछ भी इस अधिनियम के प्रवर्तन से दो वर्ष की अवधि के लिए ऐसी संस्था पर लागू नहीं होगा, जिसके नाम के साथ “विश्वविद्यालय” शब्द इसके प्रवर्तन से ठीक पूर्व जुड़ा था।”

5. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुसार और यूजीसी की सलाह पर एतद्वारा यह अधिसूचना जारी करके “निट्टे विश्वविद्यालय” के नाम से “विश्वविद्यालय” शब्द का विलोपन करके इसका नाम बदलकर “निट्टे” करती है। “निट्टे”, अपने नाम में “विश्वविद्यालय” प्रत्यय शब्द का उपयोग नहीं करेगा लेकिन इसके आगे कोष्ठकों के भीतर “समविश्वविद्यालय” प्रत्यय शब्द का उल्लेख कर सकता है।

6. “निट्टे” दिनांक 04.06.2008 की पूर्व अधिसूचना में उल्लिखित अन्य शर्तों का पालन करता रहेगा।

संजय कुमार सिन्हा

संयुक्त सचिव

सं.एफ. 9-2/2003-यू.3(ए).—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 13.06.2007 की अधिसूचना सं. 9-2/2003-यू.3 के तहत “संतोष विश्वविद्यालय”, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, जिसमें संतोष मेडीकल कॉलेज, गाजियाबाद; और संतोष डेंटल कॉलेज, गाजियाबाद शामिल हैं, को यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा एक वर्ष बाद इसके कार्य निष्पादन के मूल्यांकन हेतु समीक्षा करने और यूजीसी विशेषज्ञ समिति, जिसमें वास्तविक रूप से इसका दौरा और निरीक्षण किया है, द्वारा बताई गई कमियों को दूर किए जाने संबंधी किए गए अनुपालन की जांच करने के अध्याधीन “सम-विश्वविद्यालय” घोषित किया था। यह इस शर्त के अध्याधीन था कि यह घोषणा, इस मंत्रालय और यूजीसी को सूचित करते हुए उसके द्वारा नीचे यथा विनिर्धारित शर्तों का अनुपालन करने के बाद प्रवृत्त होगी:



- i. छात्रों के भविष्य, संकाय सदस्यों, कर्मचारियों के हित में और उच्चतर शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए, संतोष मेडीकल कॉलेज, गाजियाबाद और संतोष डेंटल कॉलेज, गाजियाबाद, दोनों की चल और अचल आस्तियां संतोष विश्वविद्यालय के प्रबंधन के लिए बनाए गए और इस रूप में पंजीकृत न्यास/सोसायटी को कानूनी तौर पर अंतरित और निविष्ट की जाएंगी; और
  - ii. संतोष मेडीकल कॉलेज, गाजियाबाद और संतोष डेंटल कॉलेज, गाजियाबाद को उनके संबंधन विश्वविद्यालय अर्थात् चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश से संबद्धता समाप्त करनी होगी।
3. और जबकि, यूजीसी, इस मंत्रालय की दिनांक 13.06.2007 की अधिसूचना द्वारा यथाअपेक्षित संतोष विश्वविद्यालय (समविश्वविद्यालय) के कार्यकरण की समीक्षा करने की प्रक्रिया में है।
4. और इसके अतिरिक्त जबकि, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड बनाम रबिंशंकर पात्रो एवं अन्य द्वारा दायर सिविल अपील सं. 17869-17870/2017 (एसएलपी (सी) सं. 19807-19808/2012 से उत्पन्न) और विजय कुमार एवं अन्य बनाम करतार सिंह एवं अन्य नामक सिविल अपील सं. 17902-17905/2017 (एसएलपी सी सं. 35793-96/2012 से उत्पन्न) में अपने दिनांक 03.11.2017 के आदेश में यह निर्णय दिया था कि यूजीसी, आज से एक माह के भीतर यूजीसी अधिनियम की धारा 23 के कार्यान्वयन और समविश्वविद्यालयों को “विश्वविद्यालय” शब्द का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के समुचित उपाय करेगा।
5. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 23 में प्रावधान है “किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के द्वारा अथवा उसके तहत स्थापित या समाविष्ट विश्वविद्यालय से इतर कोई भी संस्था, चाहे कॉर्पोरेट निकाय है या नहीं, किसी भी ढंग से, जो भी हो, अपने नाम के साथ “विश्वविद्यालय” शब्द जोड़ने की पात्र नहीं होगी: परंतु इस धारा में दिया गया कुछ भी इस अधिनियम के प्रवर्तन से दो वर्ष की अवधि के लिए ऐसी संस्था पर लागू नहीं होगा, जिसके नाम के साथ “विश्वविद्यालय” शब्द इसके प्रवर्तन से ठीक पूर्व जुड़ा था।”
6. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार और यूजीसी की सलाह पर एतदद्वारा यह अधिसूचना जारी करते हुए “संतोष विश्वविद्यालय” के नाम से “विश्वविद्यालय” शब्द का विलोपन कर इसका नाम बदलकर “संतोष” करती है। “संतोष”, अपने नाम में “विश्वविद्यालय” प्रत्यय का उपयोग नहीं करेगा लेकिन इसके आगे कोष्ठकों के भीतर “समविश्वविद्यालय” प्रत्यय शब्द का उल्लेख कर सकता है।
7. “संतोष” दिनांक 13.06.2007 की पूर्व अधिसूचना में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों का पालन करता रहेगा।

संजय कुमार सिन्हा

संयुक्त सचिव

सं.एफ. 9-12/2001-यू.3(ए).—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 06.05.2002 की अधिसूचना सं. 9-12/2001-यू.3 के द्वारा सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पुणे, जिसमें (i) सिंबायोसिस कंप्यूटर अध्ययन और अनुसंधान संस्थान; (ii) सिंबायोसिस व्यवसाय प्रबंधन संस्थान; और (iii) सिंबायोसिस सोसायटीज लॉ कॉलेज शामिल हैं, को इस अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से “समविश्वविद्यालय” घोषित किया था।

3. और इसके अतिरिक्त जबकि, यूजीसी की सिफारिश पर, केन्द्र सरकार ने दिनांक 10.11.2006 की अपनी अधिसूचना सं. 9-12/2006-यू.3(ए) के जरिए निम्नलिखित दस संस्थाओं को सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, (समविश्वविद्यालय), पुणे के दायरे में शामिल किया था:

- i. सिंबायोसिस प्रबंधन और मानव संसाधन विकास केन्द्र
- ii. सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय संस्थान

- iii. सिंबायोसिस दूरसंचार प्रबंधन संस्थान
- iv. सिंबायोसिस प्रबंधन अध्ययन संस्थान
- v. सिंबायोसिस जनसंचार संस्थान
- vi. सिंबायोसिस प्रचालन प्रबंधन संस्थान
- vii. सिंबायोसिस सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र
- viii. सिंबायोसिस जिओ इनफॉर्मेटिक्स संस्थान
- ix. सिंबायोसिस स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान
- x. सिंबायोसिस डिजाइन संस्थान

4. और जबकि, इस मंत्रालय की दिनांक 25.03.2008 की अधिसूचना सं. 9-11/2008-यू3(ए) के जरिए 'सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र' का नाम बदलकर 'सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय' कर दिया गया था।

5. और इसके अलावा जबकि, यूजीसी की सिफारिश पर, केन्द्र सरकार ने दिनांक 16.04.2008 की अपनी अधिसूचना सं. 10-6/2007-यू3 (ए) के जरिए 'सिंबायोसिस प्रबंधन संस्थान', बंगलौर, 'सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय' (सम-विश्वविद्यालय) का ऑफ-कैंपस केन्द्र होगा, अनुमोदित किया है, यह इस शर्त के अधीन कि संस्थान, कार्यात्मक और सेक्टरल क्षेत्रों जैसे विपणन, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, प्रचालनात्मक प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन आदि में प्रस्तावित एम.बी.ए. पाठ्यक्रम के संबंध में 150 छात्रों की प्रवेश क्षमता बनाए रखेगा।

6. और इसके अतिरिक्त जबकि, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड बनाम रबिंशंकर पात्रो एवं अन्य द्वारा दायर सिविल अपील सं. 17869-17870/2017 (एसएलपी (सी) सं. 19807-19808/2012 से उत्पन्न) और विजय कुमार एवं अन्य बनाम करतार सिंह एवं अन्य शीर्षक सिविल अपील सं. 17902-17905/2017 (एसएलपी सी सं. 35793-96/2012 से उत्पन्न) में अपने दिनांक 03.11.2017 के आदेश में यह निर्णय दिया था कि यूजीसी, आज से एक माह के भीतर यूजीसी अधिनियम की धारा 23 के कार्यान्वयन और समविश्वविद्यालयों को "विश्वविद्यालय" शब्द का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के समुचित उपाय करेगा।

7. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 23 में प्रावधान है "किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के द्वारा अथवा उसके तहत स्थापित या समाविष्ट विश्वविद्यालय से इतर कोई भी संस्था, चाहे कॉर्पोरेट निकाय हो या नहीं, किसी भी तरह से, चाहे जो हो, अपने नाम के साथ "विश्वविद्यालय" शब्द जोड़ने की पात्र नहीं होगी; परंतु इस धारा में दिया गया कुछ भी इस अधिनियम के प्रवर्तन से दो वर्ष की अवधि के लिए ऐसी संस्था पर लागू नहीं होगा, जिसके नाम के साथ "विश्वविद्यालय" शब्द इसके प्रवर्तन से ठीक पूर्व जुड़ा था।"

8. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार और यूजीसी की सलाह पर एतद्वारा यह अधिसूचना जारी करके 'सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय' के नाम से "विश्वविद्यालय" शब्द का विलोपन करके इसका नाम बदलकर 'सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय' करती है। 'सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय', अपने नाम में "विश्वविद्यालय" प्रत्यय शब्द का उपयोग नहीं करेगा लेकिन इसके आगे कोष्ठकों के भीतर "समविश्वविद्यालय" प्रत्यय शब्द का उल्लेख कर सकता है।

9. 'सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय' इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना में उल्लिखित अन्य शर्तों का पालन करता रहेगा।

संजय कुमार सिन्हा

संयुक्त सचिव

सं.एफ. 9-11/2007-यू3(ए).—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 27.02.2008 की अधिसूचना सं. 9-11/2007-यू.3(ए) के जरिए “ऐनेपोया विश्वविद्यालय, मंगलौर, कर्नाटक, जिसमें ऐनेपोया डेंटल कॉलेज, मंगलौर कॉलेज शामिल हैं, को इसके संबद्ध विश्वविद्यालय अर्थात् राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक, बेंगलूर से इस कॉलेज की संबद्धता समाप्त होने की तारीख से “समविश्वविद्यालय” घोषित किया था।

3. और इसके अतिरिक्त जबकि, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कांफरिशन लिमिटेड बनाम रबि शंकर पात्रो एवं अन्य द्वारा दायर सिविल अपील सं. 17869-17870/2017 (एसएलपी (सी) सं. 19807-19808/2012 से उत्पन्न) और विजय कुमार एवं अन्य बनाम करतार सिंह एवं अन्य शीर्षक सिविल अपील सं. 17902-17905/2017 (एसएलपी सी सं. 35793-96/2012 से उत्पन्न) में अपने दिनांक 03.11.2017 के आदेश में यह निर्णय दिया था कि यूजीसी, आज से एक माह के भीतर यूजीसी अधिनियम की धारा 23 के कार्यान्वयन और समविश्वविद्यालयों को “विश्वविद्यालय” शब्द का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के समुचित उपाय करेगा।

4. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 23 में प्रावधान है “किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के द्वारा अथवा उसके तहत स्थापित या समाविष्ट विश्वविद्यालय से इतर कोई भी संस्था, चाहे कॉर्पोरेट निकाय हो या नहीं, किसी भी तरह से, चाहे जो हो, अपने नाम के साथ “विश्वविद्यालय” शब्द जोड़ने की पात्र नहीं होगी; परंतु इस धारा में दिया गया कुछ भी इस अधिनियम के प्रवर्तन से दो वर्ष की अवधि के लिए ऐसी संस्था पर लागू नहीं होगा, जिसके नाम के साथ “विश्वविद्यालय” शब्द इसके प्रवर्तन से ठीक पूर्व जुड़ा था।”

5. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 23 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुसार और यूजीसी की सलाह पर एतद्वारा यह अधिसूचना जारी करके “ऐनेपोया विश्वविद्यालय” के नाम से “विश्वविद्यालय” शब्द का विलोपन करके इसका नाम बदलकर “ऐनेपोया” करती है। “ऐनेपोया”, अपने नाम में “विश्वविद्यालय” प्रत्यय शब्द का उपयोग नहीं करेगा लेकिन इसके आगे कोष्ठकों के भीतर “समविश्वविद्यालय” प्रत्यय शब्द का उल्लेख कर सकता है।

6. “ऐनेपोया” दिनांक 27.02.2008 की पूर्व अधिसूचना में उल्लिखित अन्य शर्तों का पालन करता रहेगा।

संजय कुमार सिन्हा

संयुक्त सचिव

आईसीआर विभाग

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2018

सं.एफ.10-3/2017-यू.3 (ए).—जबकि, केंद्रीय सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह से, किसी उच्चतर शिक्षा संस्था को सम विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 20.02.2009 की अधिसूचना सं.9-42/2006-यू3(ए) द्वारा ‘कोनेरु लक्ष्मैया शिक्षा प्रतिष्ठान’, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन, अनंतिम रूप से पांच वर्षों की अवधि के लिए, उक्त अधिनियम के उद्देश्यार्थ ‘विश्वविद्यालय संस्था’ घोषित किया था।

- i. कोनेरु लक्ष्मैया शिक्षा प्रतिष्ठान में उसकी संघटक शिक्षण इकाई के रूप में कोनेरु लक्ष्मैया इंजीनियरिंग कॉलेज, ग्रीनफील्ड्स, कुंचापल्ली पोस्ट, वड्डेश्वरम, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश शामिल होगा;
- ii. कोनेरु लक्ष्मैया शिक्षा प्रतिष्ठान, कोनेरु लक्ष्मैया इंजीनियरिंग कॉलेज के अपने संबद्ध विश्वविद्यालय अर्थात् आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, नागार्जुन नगर, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश से संबंधन समाप्त होने की तारीख से ‘सम विश्वविद्यालय संस्था’ होगी;
- iii. उक्त घोषणा में केवल वे शैक्षिक पाठ्यक्रम शामिल होंगे जो आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय के संबंधन के तहत उक्त कोनेरु लक्ष्मैया इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा आयोजित किए जाते हैं और जो संबंधित उपयुक्त सांविधिक परिषद (दों) (जैसे एआईसीटीई आदि) और यूजीसी के मानदंडों के अनुसार भविष्य में प्रारंभ हो सकते हैं;

- iv. कोनेरु लक्ष्मैया शिक्षा प्रतिष्ठान अपने क्षेत्राधिकार के तहत, केवल अगले शैक्षिक वर्ष अर्थात् 2009-10 से कोनेरु लक्ष्मैया इंजीनियरिंग कॉलेज के अनुमोदित शैक्षिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के लिए विद्यार्थियों को दाखिला देगा।
- v. कोनेरु लक्ष्मैया शिक्षा प्रतिष्ठान को दिए गए 'सम विश्वविद्यालय' के दर्जे की समीक्षा पांच वर्ष के बाद की जाएगी।
- vi. कोनेरु लक्ष्मैया शिक्षा प्रतिष्ठान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और यूजीसी द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानकों का पालन करेगा।

3. और आगे, जबकि केन्द्र सरकार, यूजीसी की सलाह पर, एतद्वारा कोनेरु लक्ष्मैया शिक्षा प्रतिष्ठान, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश को इस मंत्रालय की दिनांक 11 जुलाई, 2017 की अधिसूचना संख्या 9-42/2006-यू3(ए) द्वारा और यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2016 और समय-समय पर इसमें किए गए संशोधनों, यदि कोई हों, की शर्तों के अध्यधीन और पांच वर्षों की अवधि अर्थात् 20.02.2014 से 19.02.2019 तक के लिए सम विश्वविद्यालय के दर्जे को बढ़ाने/विनियमित करने हेतु अनुमोदन प्रदान करती है। यह अधिसूचना निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अध्यधीन होगी:

- i. कोनेरु लक्ष्मैया शिक्षा प्रतिष्ठान विश्वविद्यालय शब्द को, जहां कहीं भी प्रयोग किया जा रहा है, को सम विश्वविद्यालय शब्द से प्रतिस्थापित करेगा और यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2016 के अनुसार, जो भी अपेक्षित हो, अन्य आवश्यक संशोधन करेगा।
- ii. कोनेरु लक्ष्मैया शिक्षा प्रतिष्ठान यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा दिये सुझावों पर अमल करेगा और विसंगतियों को 6 माह की अवधि के भीतर दूर करेगा और दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अनुपालन रिपोर्ट को यूजीसी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- iii. कोनेरु लक्ष्मैया शिक्षा प्रतिष्ठान अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, विद्यार्थियों को कोनेरु लक्ष्मैया इंजीनियरिंग कॉलेज के अनुमोदित पाठ्यक्रम/कार्यक्रमों या किसी अन्य पाठ्यक्रम, जो यूजीसी और संबद्ध सांविधिक परिषद (दो) द्वारा अनुमोदित हों, जहां कहीं भी अपेक्षित हो, प्रवेश देगा। यह संबंधित यूजीसी और सांविधिक परिषदों के अनुमोदन के बिना बी.फार्मा, बीएफए और बीबीए-एलएलबी पाठ्यक्रम और ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों का दाखिला नहीं करेगा।

IV. यूजीसी की सलाह पर और उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने के बाद सम-विश्वविद्यालय के दर्जे को आगे बढ़ाया जाएगा।

4. और जबकि कोनेरु लक्ष्मैया शिक्षा प्रतिष्ठान, विजयवाड़ा, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश ने अजीजनगर, मोड़नाबाद रोड, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में एक ऑफ-कैंपस सेंटर खोलने हेतु दिनांक 19 जून, 2017 को आवेदन प्रस्तुत किया था।

5. और जबकि, यूजीसी ने अपनी विशेषज्ञ समिति के साथ ही साथ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) की विशेषज्ञ समिति की सहायता से आवेदन की जांच की। दोनों समितियों की रिपोर्ट को दिनांक 04.09.2017 को आयोजित इसकी 525वीं बैठक (मद सं.2.01) में आयोग के समक्ष रखा गया था जिसमें निम्नलिखित संकल्प लिए गए हैं:

“आयोग ने संकल्प लिया कि कोनेरु लक्ष्मैया शिक्षा प्रतिष्ठान (सम-विश्वविद्यालय), वड्डेश्वरम, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश द्वारा हैदराबाद में एक ऑफ-कैंपस सेंटर खोलने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव को यूजीसी/एआईसीटीई विजिटिंग समिति द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार अनुपालन रिपोर्ट की प्रस्तुत करने के अध्यधीन अनुमोदित किया जाता है।”

6. और आगे जबकि, दोनों समितियों की रिपोर्ट की मंत्रालय में यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2016 के अनुसार जांच की गई थी और यूजीसी से कुछ स्पष्टीकरण/सूचनाएं मांगी गई थी। तदनुसार, यूजीसी ने कोनेरु लक्ष्मैया शिक्षा प्रतिष्ठान, विजयवाड़ा, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश को मंत्रालय द्वारा उठाए गए मुद्दे की जांच करने के लिए एक सदस्यीय समिति को भेजा था। एक सदस्यीय समिति की रिपोर्ट आयोग के समक्ष दिनांक 22.12.2017 को आयोजित इसकी 527वीं बैठक में (मद सं. 3.01) में रखा गया था जिसमें आयोग ने समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और सत्यापन रिपोर्ट को अनुमोदित किया था।

7. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम 1956, की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, यूजीसी की सलाह पर, कोनेरु लक्ष्मैया शिक्षा प्रतिष्ठान, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश को अजीजनगर, मोड़नाबाद रोड, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में निम्नलिखित पाठ्यक्रमों हेतु भावी तारीख में शुरू करने की एतद्वारा अनुमति प्रदान करती है:

- i. कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग
- ii. इलेक्ट्रॉनिक और संचार इंजीनियरिंग
- iii. इलेक्ट्रॉनिक और कम्प्यूटर इंजीनियरिंग

## iv. बिजनैस एप्लिकेशन में स्नातकोत्तर

8. उपर्युक्त पैरा 7 में की गई घोषणा यूजीसी द्वारा द्विवार्षिक आधार पर आगे छः वर्षों के लिए कैंपस की समीक्षा के अध्यक्षीन होगी और आगामी पांच वर्षों के बाद यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2016 के तहत समय-समय यथा संशोधित यथा-निर्धारित समीक्षा के अध्यक्षीन होगी। उपरोक्त अनुमति आगे इस अधिसूचना की पृष्ठांकन की क्रम सं. 5 में निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने के अधीन होगी।

संजय कुमार सिन्हा

संयुक्त सचिव

## यू.3(ए) अनुभाग

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2018

सं.एफ. 9-1/99-यू.3(ए)खंड-2.—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर शिक्षा संस्था को सम-विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 21.08.2001 की अधिसूचना सं.9-9/99-यू.3 के तहत उपर्युक्त अधिनियम के उद्देश्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद को पांच वर्ष बाद समीक्षा के अध्यक्षीन तत्काल प्रभाव से सम-विश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित किया था।

3. और जबकि, यूजीसी ने अपनी विशेषज्ञ समिति की सहायता से सम-विश्वविद्यालय के कार्यपद्धति की समीक्षा की थी। समिति की रिपोर्ट को आयोग की दिनांक 24.08.2017 को आयोजित 524वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया था जिसमें निम्नलिखित संकल्प पारित किया था:

"यूजीसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद आयोग ने प्रस्ताव अनुमोदित किया था। इस प्रस्ताव को आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु एमएचआरडी को अग्रेषित करने का भी निर्णय लिया गया था। इसके अतिरिक्त, संस्थान को एक वर्ष के भीतर अपने संगम जापन आदि को यूजीसी विनियम, 2016 के अनुरूप बनाने का निदेश देने का भी निर्णय लिया गया था"

4. अब, इसलिए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर इस शर्त के अध्यक्षीन कि संस्था अपने संगम जापन/नियमों में यूजीसी (सम-विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2016, (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुसार संशोधन करेगी, दिनांक 21.08.2006 से "अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान", के समवत विश्वविद्यालय दर्जे को एतदद्वारा बढ़ाती/विनियमित करती है।

5. "अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान", हैदराबाद द्वारा दिनांक 21.08.2001 की पूर्व अधिसूचना में उल्लिखित सभी अन्य शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।

संजय कुमार सिन्हा

संयुक्त सचिव

## आईसीआर विभाग

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2018

सं.एफ. 10-12/2016-यू.3(ए).—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी के परामर्श से किसी उच्चतर अधिगम संस्था को समविश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी के परामर्श पर अपनी दिनांक 11.01.2003 की अधिसूचना सं. 9-39/2001-यू.3(ए) के जरिए डा. डीवाई पाटिल विद्यापीठ, पिंपरी, पुणे जिसमें डा. डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल तथा अनुसंधान केन्द्र, पुणे शामिल हैं, को निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन समविश्वविद्यालय घोषित किया था:

- i यह यूजीसी द्वारा सम-विश्वविद्यालयों को समय-समय पर लागू किए जाने वाले दिशानिर्देशों/अनुदेशों का अनुपालन करेगा।
- ii समविश्वविद्यालय का दर्जा केवल पद्मश्री डॉ. डी.वाई. पाटिल चिकित्सा कॉलेज, अस्पताल तथा अनुसंधान केन्द्र, पिंपरी, पुणे के संबंध में स्वीकृत है और भारत सरकार द्वारा डॉ. डी.वाई. पाटिल विद्यापीठ, पिंपरी की अन्य किसी संस्थाओं के संबंध में प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। यह स्थिति डॉ. डीवाई पाटिल विद्यापीठ, पिंपरी, पुणे द्वारा उसके सभी परिपत्र, विज्ञापन, विवरणिका इत्यादि में स्पष्ट की जाएगी।

3. और इसके अतिरिक्त जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने अपनी दिनांक 20.09.2006 की अधिसूचना सं. 9.39/2001-यू.3 के तहत निम्नलिखित तीन संस्थाओं को डॉ. डी.वाई. पाटिल विद्यापीठ (समविश्वविद्यालय) पिंपरी, पुणे के कार्यक्षेत्र में रखा था:

- i डॉ. डी.वाई. पाटिल डेंटल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, पिंपरी, पुणे (महाराष्ट्र)
- ii पद्मश्री डॉ. डी.वाई. पाटिल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, पिंपरी, पुणे (महाराष्ट्र)
- iii पद्मश्री डॉ. डी.वाई. पाटिल कॉलेज ऑफ फिजियोथैरेपी, (महाराष्ट्र) पिंपरी, पुणे (महाराष्ट्र)

4. और जबकि, समविश्वविद्यालय ने दिनांक 29.03.2017 को डॉ. डी.वाई. पाटिल विद्यापीठ (समविश्वविद्यालय), पुणे, महाराष्ट्र के दायरे के तहत डॉ. डी.वाई. पाटिल कॉलेज ऑफ आयुर्वेद और अनुसंधान केन्द्र, पिंपरी, पुणे और डॉ. डी.वाई. पाटिल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान केन्द्र, पिंपरी, पुणे को समावेशित करने के लिए एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था। यह आवेदन-पत्र यूजीसी को यूजीसी (विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2016 के अनुसार जांच के लिए और मंत्रालयों को परामर्श देने के लिए अग्रेषित किया गया था।

5. और जबकि, यूजीसी ने अपनी विशेषज्ञ समिति जिसमें भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय परिषद और केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद के नामित शामिल थे, की सहायता से आवेदन की जांच की थी। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को आयोग के समक्ष उसकी दिनांक 22.12.2017 को आयोजित 527वीं बैठक में (मद संख्या 2.02) रखा गया था जिसमें निम्नलिखित संकल्प पारित किया गया था:

“विचार किया गया और इस शर्त पर अनुमोदित किया गया, कि विजिटिंग विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों, यदि कोई हों, पर 6 माह की अवधि के भीतर कार्रवाई की जाएगी और दस्तावेजी प्रमाण के साथ अनुपालन रिपोर्ट यूजीसी के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी।

6. और आगे जबकि, यूजीसी ने अपने दिनांक 20.01.2018 के पत्र संख्या 30-1/2017 (सीपीपी-1/डीयू) के जरिए सूचित किया है कि समविश्वविद्यालय ने यूजीसी विजिटिंग विशेषज्ञ समिति द्वारा बताए गए सुझावों का अनुपालन किया है।

- क) डॉ. डी.वाई. पाटिल कॉलेज ऑफ आयुर्वेद और अनुसंधान केन्द्र, पिंपरी, पुणे, और
- ख) डॉ. डी.वाई. पाटिल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान केन्द्र, पिंपरी, पुणे।

7. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, यूजीसी की सलाह पर एतद्वारा डॉ. डी.वाई. पाटिल विद्यापीठ (समविश्वविद्यालय), पिंपरी, पुणे के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित दो संस्थाओं को उनके संबंधन विश्वविद्यालय अर्थात् महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नासिक से संबंधता समाप्त होने की तारीख से, समविश्वविद्यालय संस्थाओं के रूप में शामिल करने हेतु अपना अनुमोदन प्रदान करती है।

8. उक्त अनुमति इस अधिसूचना के पृष्ठांकन की क्रम सं. 8 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन है।

संजय कुमार सिन्हा

संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
(DEPARTMENTAL OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi, the 22nd March, 2018

No. 11034/48/2014-O.L.(Policy).—The following modification have been made in Rajabhasha Awards given by Department of Official Language from the year 2018-19:

- (a) For consideration under Rajbhasha Kirti Puraskar, the number of Officials in Ministry/Department/PSU/Autonomous Body/Bank etc should be minimum 30.
- (b) In Office Memorandum no. 11034/48/2014-O.L.(Policy) dated 25.03.2014 which is related to Rajbhasha Gaurav Puraskar:
  - (i) The 10 Consolidation Prizes awarded as per point 'A-(4)' and I Consolation Prize awarded as per point 'B' are to be discontinued from the year 2017.
  - (ii) Sub-point (v) is to be read under point 'B-(5)' which is as follows "The retired officials can send their book directly to the Department of Official Language along with a copy of PPO."
  - (iii) Sub-point (xi) is to be read under General Condition mentioned under points 'A-(6)' & 'B-(4)' which is as follow "Under the award schemes, only books with ISBN number will be considered."
- (c) Officials who score marks less than 60% will not be considered for the awards under Rajasthan Kirti/Regional Awards.

DR. BIPIN BEHARI

Jt. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE  
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS WELFARE)

New Delhi, the 14th March, 2018

No.8-65/2017-PP.II.—In partial modification of Government of India, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare Notification No.8-97/91-PP.I dated 26.11.1993, as amended from time to time, it is hereby notified for general information that the following entries shall be included by way of addition or replacement under the relevant heads specifying officers, by designation, who are authorized to inspect, fumigate or disinfect and grant phytosanitary certificates in respect of plants and plant materials intended for export to other countries, which require such certificates:

I. Central Government

- (lxvii) The Officer-in-Charge,  
Plant Quarantine Station,  
Madurai Airport (Tamil Nadu),  
[Code No. 'C' (PPQS) 1 (67)]

II. STATES/UTS:

GUJARAT

- (v) Deputy Director of Agriculture(PQ),  
Surat,  
(Gujarat)  
{ Code No. 'S'(GUJ) 5 }

MAHARASHTRA

- (xii) Deputy Director of Agriculture,  
Thane,  
(Maharashtra)  
{ Code No. 'S'(MAH) 12 }
- (xiii) Deputy Director of Agriculture,  
Ahmednagar,  
(Maharashtra)  
{ Code No. 'S'(MAH) 13 }
- (xiv) Deputy Director of Agriculture,  
Satara,  
(Maharashtra)  
{ Code No. 'S'(MAH) 14 }
- (xv) Deputy Director of Agriculture,  
Latur  
(Maharashtra)  
{ Code No. 'S'(MAH) 15 }
- (xvi) Deputy Director of Agriculture,  
Jalna,  
(Maharashtra)  
{ Code No. 'S'(MAH) 16 }

Dr. B. RAJENDER

Jt. Secy.

Note: The original notification was issued by Department of Agriculture & Cooperation vide notification no. 8-97/91-PP.I dated 26.11.1993 and subsequently modified vide notification no. 8-97/91-PP.I dated 25.11.97, notification no. 8-70/98-PP.I dated 30.09.1999, notification no. 8-86/2000-PP.I dated 06.11.2001, notification no. 8-86/2000-PP.I dated 06.05.2002, notification no. 8-86/2000-PP.I dated 30.05.2002, notification no. 8-33/2003-PP.I dated 7.6.2004, notification no.8-217/2004-PP.I(pt.) dated 11.05.05, notification no.8-217/2004-PP.I(pt.) dated 20.06.05, notification no.8-217/2004-PP.I(pt.) dated 8.12.05, notification no.8-217/2004-PP.I(pt.) dated 9.1.06, notification no.8-217/2004-PP.I(pt.) dated 26<sup>th</sup> December, 2011, notification no. 8-217/2004-PP.I(pt.) dated 30<sup>th</sup> January, 2013, notification no. 8-217/2004-PP.I(pt.) dated 6<sup>th</sup> July, 2015, notification no. 8-217/2004-PP.I(pt.) dated 21<sup>st</sup> June, 2016, notification no. 8-217/2004-PP.I(pt.) dated 12<sup>th</sup> January, 2017 and notification no. 8-65/2017-PP.II dated 13<sup>th</sup> April, 2017.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

(BUDGET DIVISION)

RESOLUTION

New Delhi, the 11th April, 2018

F.No. 5(1)-B(PD)/2018.—It is announced for general information that during the year 2018-2019, accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 7.6% (Seven point six per cent) w.e.f. 1st April, 2018 to 30th June, 2018. This rate will be in force w.e.f. 1st April, 2018. The funds concerned are:—

1. The General Provident Fund (Central Services).
2. The Contributory Provident Fund (India).



3. The All India Services Provident Fund.
  4. The State Railway Provident Fund.
  5. The General Provident Fund (Defence Services).
  6. The Indian Ordnance Department Provident Fund.
  7. The Indian Ordnance Factories Workmen's Provident Fund.
  8. The Indian Naval Dockyard Workmen's Provident Fund.
  9. The Defence Services Officers Provident Fund.
  10. The Armed Forces Personnel Provident Fund.
2. Ordered that the Resolution be published in Gazette of India.

ANJANA VASHISHTHA

Dy. Secy. (Budget)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT  
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 25th August, 2017

No.F.9-14/2011-U.3 (A).—**Whereas**, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as a Deemed to be University;

2. **And whereas**, a proposal was received in the year 2011 for grant of Deemed to be University status (under de novo category) to Kalinga Institute of Social Sciences (KISS), Bhubaneswar, Odisha, under Section 3 of the UGC Act, 1956;

3. **And whereas**, the application was forwarded to UGC for examination and advice as per the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2010. In the meanwhile, the new Regulations i.e. UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016 have come into effect in supersession to UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2010.

4. **And further whereas**, as per the advice of UGC, a supplementary proposal was submitted by the Institute to the Ministry of Human Resource Development in accordance with UGC Regulations, 2016. The supplementary application was also forwarded to UGC for examination and advice.

5. **And whereas**, UGC constituted an Expert Committee to recommend whether Kalinga Institute of Social Sciences (KISS), Bhubaneswar is an Institution with the focus on teaching and research in unique and 'emerging areas of knowledge' not being perused by existing institutions and its proposal may be considered under de-novo category. The Committee unanimously recommended that the proposal of Kalinga Institute of Social Sciences (KISS), Bhubaneswar for grant of Deemed to be University status under de-novo category can be considered.

6. **And further whereas**, as required under the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016, UGC constituted another Expert Committee for on the site inspection for verification of infrastructure and other facilities available with the Institute.

7. **And whereas**, the report of UGC Visiting Committee was considered and approved by the UGC in its 522nd meeting (Item No.2.04) held on 28th March, 2017.

8. **And further whereas**, keeping in view the report of UGC Expert Committee and clarifications from the Institute, the Ministry vide its letter No.9-14/2011-U3(A) dated 19<sup>th</sup> July, 2017 agreed the proposal in principle with the following conditions:

- i. The Institute shall submit documentary proof in respect of de-linking of proposed Deemed to be University from the School being run by KISS.
- ii. The Institute shall appoint required numbers of faculties for the seven proposed Departments as per UGC norms.
- iii. The Institute shall submit the details of total land allotted in the name of proposed KISS Deemed to be University as the land details earlier submitted by KISS was at variance with the land details given in the UGC Expert Committee Report.
- iv. The Institute shall submit a report clarifying whether it is fully prepared to start the Courses proposed by it.

9. **And whereas**, the Institute submitted its compliance report for fulfilment of above conditions. Further, UGC was requested to look into the compliance report and clarify whether Kalinga Institute of Social Sciences (KISS), Bhubaneswar has fulfilled all the conditions for notification as Deemed to be University under de-novo category. UGC vide its letter No.35-1/2011 (CPP-I/DU) dated 2<sup>nd</sup> August, 2017 clarified that the Institute has fulfilled all the conditions as mentioned in this Ministry's letter No.9-14/2011-U3(A) dated 19<sup>th</sup> July, 2017.

10. **Now, therefore**, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, hereby declare that Kalinga Institute of Social Sciences (KISS), Bhubaneswar, Odisha, shall be deemed to be a University for the purposes of the aforesaid Act for a provisional period of five years under de-novo category. The status of Deemed to be University shall be confirmed after five years based on the review report of UGC Expert Committee and the recommendation of the Commission. The Deemed to be University status to Kalinga Institute of Social Sciences (KISS), Bhubaneswar, Odisha is being granted for the following seven Departments:

- i. Department of Tribal Culture, Philosophy and Eco-Spiritualism
- ii. Department of Indigenous Knowledge, Science and Technology
- iii. Department of Comparative Tribal Linguistics and Literature
- iv. Department of Tribal Heritage and Tribal Indology
- v. Department of Comparative Indic Studies and Tribal Science
- vi. Department of Tribal Resource Management
- vii. Department of Tribal Legal Studies and Tribal Rights

11. The declaration as made in Para 10 above is further subject to fulfilment of the conditions mentioned at Sr. No.5 of the endorsement to this notification;

ISHITA ROY

Jt. Secy.

---

No.F.10-2/2017-U.3 (A).—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as a Deemed to be University;

2. **And whereas**, on the advice of the UGC, Tata Institute of Fundamental Research (TIFR), Mumbai, Maharashtra was declared as an as Institution Deemed to be University vide this Ministry's Notification No. F. 9-48/2001-U.3 dated 07.05.2002 along with the following three multi-campus:-

- i. National Centre for Radio physics, Pune
- ii. National Centre for Biological Sciences, Bangalore
- iii. Homi Bhaba Centre for Science Education, Mumbai

3. **And whereas**, the Institution Deemed to be University submitted a proposal dated 09.02.2017 to Ministry of Human Resource Development for establishment of an off-campus centre at Hyderabad with TIFR Centre for Interdisciplinary Sciences (TCIS), Hyderabad as a part of TIFR, Hyderabad;

4. **And further whereas**, the proposal has been examined by the UGC with the help of an Expert Committee in terms of the provisions of UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016. The report of the UGC Expert Committee was approved by the Commission in its 523<sup>rd</sup> meeting (Item No.2.06) held on 7<sup>th</sup> June, 2017.

5. **Now, therefore**, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the University Grants Commission (UGC), do hereby accord its approval to the Tata Institute of Fundamental Research (TIFR), Mumbai, Maharashtra to start an *off-campus centre at Hyderabad with prospective effect with TIFR Centre for Interdisciplinary Sciences (TICS) as a part of TIFR, Hyderabad.*

6. The declaration as made in Para 5 above is further subject to fulfilment of the conditions mentioned at Sr. No.5 of the endorsement to this notification and adherence to the conditions mentioned in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016 and its amendments, if any, from time to time.

ISHITA ROY

Jt. Secy.

## U.3(A) Section

New Delhi, the 11th January, 2018

No. F.9-37/2007-U3(A).—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-37/2007-U3(A) dated 29.02.2008, on the advice of UGC, had declared Shri B. M. Patil Medical College, Hospital & Research Centre, Bijapur, Karnataka as deemed to be University in the name & style of 'BLDE University' for the provisional period of five years, with effect from the date on which the aforesaid Medical College disaffiliates itself from its affiliating University viz. Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka, Bangalore. This was subject to condition that the status of deemed to be University shall be confirmed after the period of 5 years based on the inspection and assessment report of UGC's Expert Review Committee and the recommendations of the UGC thereon.

3. And whereas, UGC is in the process of reviewing the functioning of BLDE University (deemed to be University), Bijapur, Karnataka as required by this Ministry's Notification dated 29.02.2008.

4. And further whereas, the Hon'ble Supreme Court of India vide its judgment Order dated 03.11.2017 in Civil Appeal Nos. 17869-17870/2017 (arising out of SLP(C) Nos.19807-19808/2012) filed by Orissa Lift Irrigation Corp. Ltd Versus Rabi Sankar Patro & Ors. and Civil Appeal Nos.17902-17905/2017 (arising out of SLP C Nos.35793-96/2012) titled as Vijay Kumar & Ors Vs. Kartar Singh & Ors held that UGC shall take appropriate steps for implementing Section 23 of the UGC Act and restraining Deemed to be Universities from using the word 'University' within one month from today.

5. And whereas, Section 23 of the UGC Act, 1956 says "*no institution, whether a corporate body or not, other than a University established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act shall be entitled to have the word "University" associated with its name in any manner whatsoever. Provided that nothing in this section shall, for a period of two years from the commencement of this Act, apply to an institution which, immediately before such commencement, had the word "University" associated with its name*".

6. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, as per direction of Hon'ble Supreme Court, and on the advice of the UGC, do hereby change the name of "BLDE University" to "BLDE" by deleting the word 'University' from its name w.e.f. the issuance of this Notification. BLDE shall not use the word 'University' suffixed to its name but may mention the word "deemed to be university" within parenthesis suffixed thereto.

7. The other conditions mentioned in the earlier Notification dated 29.02.2008 shall continue to be adhered by BLDE.

SANJAY KUMAR SINHA

Jt. Secy.

No. F.9-34/2007-U3(A).—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-34/2007-U3(A) dated 22.07.2008, on the advice of UGC, had declared Christ College (Autonomous), Bangalore, Karnataka as deemed to be University in the name & style of 'Christ University' for the provisional period of five years, with effect from the date on which the aforesaid College disaffiliates itself from its affiliating University viz. Bangalore University. This was subject to condition that the status of deemed to be University shall be confirmed after the period of 5 years based on the inspection and assessment report of UGC's Expert Review Committee and the recommendations of the UGC thereon.

3. And whereas, UGC is in the process of reviewing the functioning of Christ University (deemed to be University), Bangalore, Karnataka as required by this Ministry's Notification dated 22.07.2008.

4. And further whereas, the Hon'ble Supreme Court of India vide its judgment Order dated 03.11.2017 in Civil Appeal Nos. 17869-17870/2017 (arising out of SLP(C) Nos.19807-19808/2012) filed by Orissa Lift Irrigation Corp. Ltd Versus Rabi Sankar Patro & Ors. and Civil Appeal Nos.17902-17905/2017 (arising out of SLP C Nos.35793-96/2012) titled as Vijay Kumar & Ors Vs. Kartar Singh & Ors held that UGC shall take appropriate steps for implementing Section 23 of the UGC Act and restraining Deemed to be Universities from using the word 'University' within one month from today.

5. And whereas, Section 23 of the UGC Act, 1956 says “*no institution, whether a corporate body or not, other than a University established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act shall be entitled to have the word “University” associated with its name in any manner whatsoever: Provided that nothing in this section shall, for a period of two years from the commencement of this Act, apply to an institution which, immediately before such commencement, had the word “University” associated with its name*”.

6. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, as per direction of Hon’ble Supreme Court, and on the advice of the UGC, do hereby change the name of “Christ University” to “Christ” by deleting the word ‘University’ from its name w.e.f. the issuance of this Notification. “Christ” shall not use the word ‘University’ suffixed to its name but may mention the words “deemed to be university” within parenthesis suffixed thereto.

7. The other conditions mentioned in the earlier Notification dated 22.07.2008 shall continue to be adhered by Christ.

SANJAY KUMAR SINHA

Jt. Secy.

---

No. F.9-48/2007-U3(A).—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-48/2007-U3(A) dated 14.08.2008, on the advice of UGC, had declared ‘Graphic Era University’, Dehradun, Uttarakhand consisting of ‘Graphic Era Institute of Technology’ as a deemed to be University for the provisional period of five years, with effect from the date on which it disaffiliates itself from its affiliating Universities viz. Uttarakhand Technical University and HNB Garhwal University. This was subject to condition that the status of deemed to be University shall be confirmed after the period of 5 years based on the inspection and assessment report of UGC’s Expert Review Committee and the recommendations of the UGC thereon.

3. And whereas, UGC is in the process of reviewing the functioning of Graphic Era University (Deemed to be University), Dehradun, Uttarakhand as required in this Ministry’s Notification dated 14.08.2008.

4. And further whereas, the Hon’ble Supreme Court of India vide its judgment Order dated 03.11.2017 in Civil Appeal Nos. 17869-17870/2017 (arising out of SLP(C) Nos.19807-19808/2012) filed by Orissa Lift Irrigation Corp. Ltd Versus Rabi Sankar Patro & Ors. and Civil Appeal Nos.17902-17905/2017 (arising out of SLP C Nos.35793-96/2012) titled as Vijay Kumar & Ors Vs. Kartar Singh & Ors held that UGC shall take appropriate steps for implementing Section 23 of the UGC Act and restraining deemed to be Universities from using the word ‘University’ within one month from today.

5. And whereas, Section 23 of the UGC Act, 1956 says “*no institution, whether a corporate body or not, other than a University established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act shall be entitled to have the word “University” associated with its name in any manner whatsoever: Provided that nothing in this section shall, for a period of two years from the commencement of this Act, apply to an institution which, immediately before such commencement, had the word “University” associated with its name*”.

6. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, as per direction of Hon’ble Supreme Court and on the advice of the UGC, do hereby change the name of “Graphic Era University” to “Graphic Era” by deleting the word ‘University’ from its name w.e.f. the issuance of this Notification. “Graphic Era” shall not use the word ‘University’ suffixed to its name but may mention the word “deemed to be university” within parenthesis suffixed thereto.

7. The other conditions mentioned in the earlier Notification dated 14.08.2008 shall continue to be adhered by “Graphic Era”.

SANJAY KUMAR SINHA

Jt. Secy.

No. F.10-17/62-U.2/U3(A)Pt.1.—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.10-17/62-U2 dated 19.06.1962, on the advice of UGC, had declared ‘Gurukula Kangri Vishwavidyalaya’, Haridwar as a deemed to be University.

3. And further whereas, the Hon’ble Supreme Court of India vide its judgment Order dated 03.11.2017 in Civil Appeal Nos. 17869-17870/2017 (arising out of SLP(C) Nos.19807-19808/2012) filed by Orissa Lift Irrigation Corp. Ltd Versus Rabi Sankar Patro & Ors. and Civil Appeal Nos.17902-17905/2017 (arising out of SLP C Nos.35793-96/2012) titled as Vijay Kumar & Ors Vs. Kartar Singh & Ors held that UGC shall take appropriate steps for implementing Section 23 of the UGC Act and restraining Deemed to be Universities from using the word ‘University’ within one month from today.

4. And whereas, Section 23 of the UGC Act, 1956 says “*no institution, whether a corporate body or not, other than a University established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act shall be entitled to have the word “University” associated with its name in any manner whatsoever: Provided that nothing in this section shall, for a period of two years from the commencement of this Act, apply to an institution which, immediately before such commencement, had the word “University” associated with its name*”.

5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, as per direction of Hon’ble Supreme Court and on the advice of the UGC, do hereby change the name of “Gurukula Kangri Vishwavidyalaya” to “Gurukula Kangri Vidyapeeth” by replacing the word ‘Vishwavidyalaya’ with ‘Vidyapeeth’ from its name w.e.f. the issuance of this Notification. “Gurukula Kangri Vidyapeeth” shall not use the word ‘University/Vishwavidyalaya’ suffixed to its name but may mention the word “deemed to be university” within parenthesis suffixed thereto.

SANJAY KUMAR SINHA

Jt. Secy.

No. F.9-57/2007-U3(A).—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-57/2007-U3(A) dated 19.12.2008, on the advice of UGC, had declared Sri Bhagawan Mahaveer Jain College, Bangalore, Karnataka as deemed to be University in the name & style of ‘Jain University’ for the provisional period of five years, with effect from the date on which the aforesaid College disaffiliates itself from its affiliating University viz. Bangalore University, Bangalore. This was subject to condition that the status of Deemed to be University shall be confirmed after the period of 5 years based on the inspection and assessment report of UGC’s Expert Review Committee and the recommendations of the UGC thereon.

3. And whereas, UGC is in the process of reviewing the functioning of Jain University (Deemed to be University), Bangalore, Karnataka as required by this Ministry’s Notification dated 19.12.2008.

4. And further whereas, the Hon’ble Supreme Court of India vide its judgment Order dated 03.11.2017 in Civil Appeal Nos. 17869-17870/2017 (arising out of SLP(C) Nos.19807-19808/2012) filed by Orissa Lift Irrigation Corp. Ltd Versus Rabi Sankar Patro & Ors. and Civil Appeal Nos.17902-17905/2017 (arising out of SLP C Nos.35793-96/2012) titled as Vijay Kumar & Ors Vs. Kartar Singh & Ors held that UGC shall take appropriate steps for implementing Section 23 of the UGC Act and restraining deemed to be Universities from using the word ‘University’ within one month from today.

5. And whereas, Section 23 of the UGC Act, 1956 says “*no institution, whether a corporate body or not, other than a University established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act shall be entitled to have the word “University” associated with its name in any manner whatsoever: Provided that nothing in this section shall, for a period of two years from the commencement of this Act, apply to an institution which, immediately before such commencement, had the word “University” associated with its name*”.

6. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, as per direction of Hon’ble Supreme Court and on the advice of the UGC, do hereby change the name of “Jain University” to “Jain” by deleting the word ‘University’ from its name w.e.f. the issuance of this Notification. “Jain” shall not use the word ‘University’ suffixed to its name but may mention the word “deemed to be university” within parenthesis suffixed thereto.

7. The other conditions mentioned in the earlier Notification dated 19.12.2008 shall continue to be adhered by “Jain”.

SANJAY KUMAR SINHA

Jt. Secy.

---

No. F.9-9/2003-U3(A).—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-9/2003-U3 dated 28.05.2008, on the advice of UGC, had declared Jagadguru Sri Shivarathreeswara University (JSSU), Mysore, Karnataka consisting of (i) J.S.S. Medical College, Mysore; (ii) J.S.S. Dental College, Mysore; (iii) J.S.S. College of Pharmacy, Mysore; and J.S.S. College of Pharmacy, Ooty (Tamil Nadu) as “deemed to be University”, provisionally for a period of five years, with effect from the date on which the aforesaid colleges disaffiliate themselves from their affiliating University viz. Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore and the Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai. This declaration was further to condition that the status of deemed to be University shall be confirmed after the period of 5 years based on the inspection and assessment report of UGC’s Expert Review Committee and the recommendations of the UGC thereon. It was made clear that J.S.S. College of Pharmacy, Ooty shall function as an Off-Campus Centre of the JSSU.

3. And further whereas, the Hon’ble Supreme Court of India vide its judgment Order dated 03.11.2017 in Civil Appeal Nos. 17869-17870/2017 (arising out of SLP(C) Nos.19807-19808/2012) filed by Orissa Lift Irrigation Corp. Ltd Versus Rabi Sankar Patro & Ors. and Civil Appeal Nos.17902-17905/2017 (arising out of SLP C Nos.35793-96/2012) titled as Vijay Kumar & Ors Vs. Kartar Singh & Ors held that UGC shall take appropriate steps for implementing Section 23 of the UGC Act and restraining Deemed to be Universities from using the word ‘University’ within one month from today.

4. And whereas, Section 23 of the UGC Act, 1956 says “*no institution, whether a corporate body or not, other than a University established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act shall be entitled to have the word “University” associated with its name in any manner whatsoever: Provided that nothing in this section shall, for a period of two years from the commencement of this Act, apply to an institution which, immediately before such commencement, had the word “University” associated with its name*”.

5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, as per direction of Hon’ble Supreme Court and on the advice of the UGC, do hereby change the name of “Jagadguru Sri Shivarathreeswara University (JSSU)”, Mysore, Karnataka to “JSS Academy of Higher Education & Research” as desired by the Institute w.e.f. the issuance of this Notification. “JSS Academy of Higher Education & Research” shall not use the word ‘University’ suffixed to its name but may mention the word “deemed to be university” within parenthesis suffixed thereto.

6. The all other conditions mentioned in the earlier Notification dated 28.05.2008 shall continue to be adhered by “JSS Academy of Higher Education & Research”.

SANJAY KUMAR SINHA

Jt. Secy.

---

No. F.9-23/2005-U3(A).—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-23/2005-U3 dated 05.01.2009, on the advice of UGC, had declared Lingaya’s Institute of Management & Technology, Faridabad as deemed to be University in the name & style of ‘Lingaya’s University’ for the provisional period of five years, with effect from the date on which the aforesaid Institute disaffiliates itself from its affiliating University viz. Maharshi Dayanand University, Rohtak, Haryana. This was subject to condition that the status of

deemed to be University shall be confirmed after the period of 5 years based on the inspection and assessment report of UGC's Expert Review Committee and the recommendations of the UGC thereon.

3. And whereas, UGC is in the process of reviewing the functioning of Lingaya's University (Deemed to be University), Faridabad as required by this Ministry's Notification dated 05.01.2009.

4. And further whereas, the Hon'ble Supreme Court of India vide its judgment Order dated 03.11.2017 in Civil Appeal Nos. 17869-17870/2017 (arising out of SLP(C) Nos.19807-19808/2012) filed by Orissa Lift Irrigation Corp. Ltd Versus Rabi Sankar Patro & Ors. and Civil Appeal Nos.17902-17905/2017 (arising out of SLP C Nos.35793-96/2012) titled as Vijay Kumar & Ors Vs. Kartar Singh & Ors held that UGC shall take appropriate steps for implementing Section 23 of the UGC Act and restraining Deemed to be Universities from using the word 'University' within one month from today.

5. And whereas, Section 23 of the UGC Act, 1956 says "*no institution, whether a corporate body or not, other than a University established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act shall be entitled to have the word "University" associated with its name in any manner whatsoever: Provided that nothing in this section shall, for a period of two years from the commencement of this Act, apply to an institution which, immediately before such commencement, had the word "University" associated with its name*".

6. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, as per direction of Hon'ble Supreme Court, and on the advice of the UGC, do hereby change the name of "Lingaya's University", Faridabad, Haryana to "Lingaya's Vidyapeeth" by replacing the word 'University' with 'Vidyapeeth' w.e.f. the issuance of this Notification. "Lingaya's Vidyapeeth" shall not use the word 'University' suffixed to its name but may mention the word "deemed to be university" within parenthesis suffixed thereto.

7. The other conditions mentioned in the earlier Notification dated 05.01.2009 shall continue to be adhered by "Lingaya's Vidyapeeth".

SANJAY KUMAR SINHA

Jt. Secy.

---

No. F.9-65/2006-U3(A).—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-65/2006-U3(A) dated 12.06.2007, on the advice of UGC, had declared Maharishi Markandeshwar University, Mullana-Ambala (Haryana) as deemed to be University consisting of the following teaching institutes, with effect from the date on which the following Institutes disaffiliate themselves from their affiliating University viz. Kurukshetra University, Kurukshetra, Haryana.

- i. M. M. Engineering College, Mullana, Ambala;
- ii. M. M. Institute of Computer Technology & Business Management (MCA), Mullana, Ambala;
- iii. M. M. College of Dental Sciences & Research, Mullana, Ambala;
- iv. M. M. Institute of Physiotherapy & Rehabilitation, Mullana, Ambala;
- v. M. M. Institute of Computer Technology & Business Management (Hotel Management), Mullana, Ambala;
- vi. M. M. Institute of Medical Sciences & Research, Mullana, Ambala;
- vii. M. M. Institute of Management, Mullana, Ambala;
- viii. M. M. College of Nursing, Mullana, Ambala;
- ix. M. M. College of Pharmacy, Mullana, Ambala; and
- x. M. M. Institute of Medical Sciences & Research Nursing College, Mullana, Ambala.

3. And further whereas, the Hon'ble Supreme Court of India vide its judgment Order dated 03.11.2017 in Civil Appeal Nos. 17869-17870/2017 (arising out of SLP(C) Nos.19807-19808/2012) filed by Orissa Lift Irrigation Corp. Ltd Versus Rabi Sankar Patro & Ors. and Civil Appeal Nos.17902-17905/2017 (arising out of SLP C Nos.35793-96/2012) titled as Vijay Kumar & Ors Vs. Kartar Singh & Ors held that UGC shall take appropriate steps for implementing Section 23 of the UGC Act and restraining Deemed to be Universities from using the word 'University' within one month from today.

4. And whereas, Section 23 of the UGC Act, 1956 says "*no institution, whether a corporate body or not, other than a University established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act shall be entitled to*

*have the word “University” associated with its name in any manner whatsoever: Provided that nothing in this section shall, for a period of two years from the commencement of this Act, apply to an institution which, immediately before such commencement, had the word “University” associated with its name”.*

5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, as per direction of Hon'ble Supreme Court and on the advice of the UGC, do hereby change the name of “Maharishi Markandeshwar University” to “Maharishi Markandeshwar” by deleting the word ‘University’ from its name w.e.f. the issuance of this Notification. “Maharishi Markandeshwar” shall not use the word ‘University’ suffixed to its name but may mention the word “deemed to be university” within parenthesis suffixed thereto.

6. The all other conditions mentioned in the earlier Notification dated 12.06.2007 shall continue to be adhered by “Maharishi Markandeshwar”.

SANJAY KUMAR SINHA

Jt. Secy.

---

No. F.9-3/2007-U3(A).—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-3/2007-U3(A) dated 21.10.2008, on the advice of UGC, had declared Manav Rachna International University, Faridabad, Haryana consisting of Career Institute of Technology & Management as a “deemed to be University” for a provisional period of five years, with effect from the date on which the aforesaid Institute disaffiliates itself from its affiliating University viz. Maharshi Dayanand University, Rohtak, Haryana. This was subject to condition that the status of Deemed to be University shall be confirmed after the period of 5 years based on the inspection and assessment report of UGC’s Expert Review Committee and the recommendations of the UGC thereon.

3. And whereas, UGC is in the process of reviewing the functioning of Manav Rachna International University (Deemed to be University), Faridabad as required by this Ministry’s Notification dated 21.10.2008.

4. And further whereas, the Hon'ble Supreme Court of India vide its judgment Order dated 03.11.2017 in Civil Appeal Nos. 17869-17870/2017 (arising out of SLP(C) Nos.19807-19808/2012) filed by Orissa Lift Irrigation Corp. Ltd Versus Rabi Sankar Patro & Ors. and Civil Appeal Nos.17902-17905/2017 (arising out of SLP C Nos.35793-96/2012) titled as Vijay Kumar & Ors Vs. Kartar Singh & Ors held that UGC shall take appropriate steps for implementing Section 23 of the UGC Act and restraining deemed to be Universities from using the word ‘University’ within one month from today.

5. And whereas, Section 23 of the UGC Act, 1956 says “*no institution, whether a corporate body or not, other than a University established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act shall be entitled to have the word “University” associated with its name in any manner whatsoever: Provided that nothing in this section shall, for a period of two years from the commencement of this Act, apply to an institution which, immediately before such commencement, had the word “University” associated with its name”.*

6. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, as per direction of Hon'ble Supreme Court and on the advice of the UGC, do hereby change the name of “Manav Rachna International University”, Faridabad, Haryana to “Manav Rachna International Institute of Research & Studies” as desired by the Institute w.e.f. the issuance of this Notification. “Manav Rachna International Institute of Research & Studies” shall not use the word ‘University’ suffixed to its name but may mention the word “deemed to be university” within parenthesis suffixed thereto.

7. The all other conditions mentioned in the earlier Notification dated 21.10.2008 shall continue to be adhered by “Manav Rachna International Institute of Research & Studies”.

SANJAY KUMAR SINHA

Jt. Secy.

---



No. F.9-42/2005-U3(A).—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-42/2005-U3(A) dated 27.06.2008, on the advice of UGC, had declared “Nehru Gram Bharati Vishwavidyalaya”, Allahabad consisting of Rajiv Gandhi P.G. College as “deemed to be University” for a provisional period of three years, with effect from the date on which the aforesaid College disaffiliates itself from its affiliating University viz. Ch. Sahuji Maharaj University, Kanpur. This was subject to condition that the status of Deemed to be University shall be confirmed after the period of 3 years based on the inspection and assessment report of UGC’s Expert Review Committee and the recommendations of the UGC thereon as well as nullification of its present shortcomings as pointed by the Expert Committee.

3. And whereas, UGC is in the process of reviewing the functioning of Nehru Gram Bharati Vishwavidyalaya (Deemed to be University) as required by this Ministry’s Notification dated 27.06.2008.

4. And further whereas, the Hon’ble Supreme Court of India vide its judgment Order dated 03.11.2017 in Civil Appeal Nos. 17869-17870/2017 (arising out of SLP(C) Nos.19807-19808/2012) filed by Orissa Lift Irrigation Corp. Ltd Versus Rabi Sankar Patro & Ors. and Civil Appeal Nos.17902-17905/2017 (arising out of SLP C Nos.35793-96/2012) titled as Vijay Kumar & Ors Vs. Kartar Singh & Ors held that UGC shall take appropriate steps for implementing Section 23 of the UGC Act and restraining Deemed to be Universities from using the word ‘University’ within one month from today.

5. And whereas, Section 23 of the UGC Act, 1956 says “*no institution, whether a corporate body or not, other than a University established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act shall be entitled to have the word “University” associated with its name in any manner whatsoever: Provided that nothing in this section shall, for a period of two years from the commencement of this Act, apply to an institution which, immediately before such commencement, had the word “University” associated with its name*”.

6. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, as per direction of Hon’ble Supreme Court and on the advice of the UGC, do hereby change the name of “Nehru Gram Bharati Vishwavidyalaya” to “Nehru Gram Bharati” by deleting the word ‘Vishwavidyalaya’ from its name w.e.f. the issuance of this Notification. “Nehru Gram Bharati” shall not use the word ‘University’ suffixed to its name but may mention the word “deemed to be university” within parenthesis suffixed thereto.

7. The all other conditions mentioned in the earlier Notification dated 27.06.2008 shall continue to be adhered by “Nehru Gram Bharati”.

SANJAY KUMAR SINHA

Jt. Secy.

No. F.9-13/2007-U3(A).—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-13/2007-U3(A) dated 04.06.2008, on the advice of UGC, had declared Nitte University, Mangalore, Karnataka consisting of A. B. Shetty Memorial Institute of Dental Sciences, Deralakatte, Mangalore as “deemed to be University”, with effect from the date on which the aforesaid Dental Institute disaffiliates itself from its affiliating University viz. Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka, Bangalore. This declaration was further subject to fulfillment of following conditions:

- i. The corpus fund of Rs. 5 Crore created by the promoting Trust, viz. Nitte Education Trust by way of Fixed Bank Deposits of Rs. 2.50 Crore each should be transferred and invested in the name of ‘Nitte University Trust’. The corpus fund should be irrevocable in nature. The fixed deposits should not be liquidated without prior consent of the UGC.
- ii. The Memorandum of Association (MoA) and Rules of ‘Nitte University’ should be in accordance and in line with the model Memorandum of Association (MoA) & Rules prescribed by the UGC, and is certified so by the UGC.

3. And further whereas, the Hon’ble Supreme Court of India vide its judgment Order dated 03.11.2017 in Civil Appeal Nos. 17869-17870/2017 (arising out of SLP(C) Nos.19807-19808/2012) filed by Orissa Lift Irrigation Corp. Ltd

Versus Rabi Sankar Patro & Ors. and Civil Appeal Nos.17902-17905/2017 (arising out of SLP C Nos.35793-96/2012) titled as Vijay Kumar & Ors Vs. Kartar Singh & Ors held that UGC shall take appropriate steps for implementing Section 23 of the UGC Act and restraining Deemed to be Universities from using the word ‘University’ within one month from today.

4. And whereas, Section 23 of the UGC Act, 1956 says “*no institution, whether a corporate body or not, other than a University established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act shall be entitled to have the word “University” associated with its name in any manner whatsoever: Provided that nothing in this section shall, for a period of two years from the commencement of this Act, apply to an institution which, immediately before such commencement, had the word “University” associated with its name*”.

5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, as per direction of Hon’ble Supreme Court and on the advice of the UGC, do hereby change the name of “Nitte University” to “Nitte” by deleting the word ‘University’ from its name w.e.f. the issuance of this Notification. “Nitte” shall not use the word ‘University’ suffixed to its name but may mention the word “deemed to be university” within parenthesis suffixed thereto.

6. All other conditions mentioned in the earlier Notification dated 04.06.2008 shall continue to be adhered by “Nitte”.

SANJAY KUMAR SINHA

Jt. Secy.

No. F.9-2/2003-U3(A).—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-2/2003-U3 dated 13.06.2007, on the advice of UGC, had declared Santosh University, Ghaziabad, Uttar Pradesh consisting of Santosh Medical College, Ghaziabad; and Santosh Dental College, Ghaziabad as “deemed to be University”, subject to review after one year by an Expert Committee of the UGC to assess its performance and also to verify its compliance with respect to rectification of the deficiencies pointed out in the reports of the UGC’s Expert Committees that visited and physically inspected them. This was further subject to condition that this declaration shall come into effect after the conditions stipulated as below have been complied with by it under intimation to this Ministry and the UGC:

- i. In the interest of future of students, members of faculty, employees and for maintaining the standards of higher education, all the moveable and immovable assets of both the Santosh Medical College, Ghaziabad and Santosh Dental College, Ghaziabad are to be legally transferred and vested with the Trust / Society formed to manage the Santosh University and registered as such; and
- ii. The Santosh Medical College, Ghaziabad and Santosh Dental College, Ghaziabad are to be disaffiliated from their affiliating University viz. Chaudhary Charan Singh University, Meerut, Uttar Pradesh.

3. And whereas, UGC is in the process of reviewing the functioning of Santosh University (Deemed to be University), Ghaziabad as required by this Ministry’s Notification dated 13.06.2007.

4. And further whereas, the Hon’ble Supreme Court of India vide its judgment Order dated 03.11.2017 in Civil Appeal Nos. 17869-17870/2017 (arising out of SLP(C) Nos.19807-19808/2012) filed by Orissa Lift Irrigation Corp. Ltd Versus Rabi Sankar Patro & Ors. and Civil Appeal Nos.17902-17905/2017 (arising out of SLP C Nos.35793-96/2012) titled as Vijay Kumar & Ors Vs. Kartar Singh & Ors held that UGC shall take appropriate steps for implementing Section 23 of the UGC Act and restraining Deemed to be Universities from using the word ‘University’ within one month from today.

5. And whereas, Section 23 of the UGC Act, 1956 says “*no institution, whether a corporate body or not, other than a University established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act shall be entitled to have the word “University” associated with its name in any manner whatsoever: Provided that nothing in this section shall, for a period of two years from the commencement of this Act, apply to an institution which, immediately before such commencement, had the word “University” associated with its name*”.

6. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, as per direction of Hon’ble Supreme Court and on the advice of the UGC, do hereby change the name of “Santosh University” to “Santosh” by deleting the word ‘University’ from its name w.e.f. the issuance of this Notification. “Santosh” shall not use the word ‘University’ suffixed to its name but may mention the word “deemed to be university” within parenthesis suffixed thereto.

7. The all other conditions mentioned in the earlier Notification dated 13.06.2007 shall continue to be adhered by “Santosh”.

SANJAY KUMAR SINHA

Jt. Secy.

No. F.9-12/2001-U3(A).—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-12/2001-U3 dated 06.05.2002, on the advice of UGC, had declared Symbiosis International Education Centre, Pune consisting of (i) Symbiosis Institute of Computer Studies & Research; (ii) Symbiosis Institute of Business Management; and (iii) Symbiosis Society’s Law college as “deemed to be University”, with effect from the date of issuance of this Notification.

3. And further whereas, on the recommendation of the UGC, the Central Government vide its Notification No. 9-12/2006-U3(A) dated 10.11.2006 included the following ten institutions under the ambit of Symbiosis International Education Centre (deemed to be University), Pune:

- i. Symbiosis Centre for Management & Human Resource Development
- ii. Symbiosis Institute of International Business
- iii. Symbiosis Institute of Telecom Management
- iv. Symbiosis Institute of Management Studies
- v. Symbiosis Institute of Mass Communication
- vi. Symbiosis Institute of Operations Management
- vii. Symbiosis Centre for Information Technology
- viii. Symbiosis Institute of Geoinformatics
- ix. Symbiosis Institute of Health Sciences
- x. Symbiosis Institute of Design

4. And whereas, the name of ‘Symbiosis International Educational Centre’ was changed to ‘Symbiosis International University’ vide this Ministry’s Notification No. 9-11/2008-U3(A) dated 25.03.2008.

5. And further whereas, on the recommendation of the UGC, the Central Government vide its Notification No. 10-6/2007-U3(A) dated 16.04.2008 approved that ‘Symbiosis Institute of Management’, Bangalore shall be an Off-Campus Centre of ‘Symbiosis International University’ (deemed to be University), subject to condition that the Institute shall maintain the student intake capacity of 150 in respect of the course of MBA proposed to be offered in the functional and sectoral areas like, Marketing, Information Technology, Finance, Operational Management, Human Resource Management, etc.

6. And further whereas, the Hon’ble Supreme Court of India vide its judgment Order dated 03.11.2017 in Civil Appeal Nos. 17869-17870/2017 (arising out of SLP(C) Nos.19807-19808/2012) filed by Orissa Lift Irrigation Corp. Ltd Versus Rabi Sankar Patro & Ors. and Civil Appeal Nos.17902-17905/2017 (arising out of SLP C Nos.35793-96/2012) titled as Vijay Kumar & Ors Vs. Kartar Singh & Ors held that UGC shall take appropriate steps for implementing Section 23 of the UGC Act and restraining Deemed to be Universities from using the word ‘University’ within one month from today.

7. And whereas, Section 23 of the UGC Act, 1956 says “no institution, whether a corporate body or not, other than a University established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act shall be entitled to have the word “University” associated with its name in any manner whatsoever: Provided that nothing in this section shall, for a period of two years from the commencement of this Act, apply to an institution which, immediately before such commencement, had the word “University” associated with its name”.

8. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, as per direction of Hon’ble Supreme Court and on the advice of the UGC, do hereby change the name of “Symbiosis International University” to “Symbiosis International” by deleting the word ‘University’ from its name w.e.f. the

issuance of this Notification. “Symbiosis International” shall not use the word ‘University’ suffixed to its name but may mention the word “deemed to be university” within parenthesis suffixed thereto.

9. All other conditions mentioned in the earlier Notifications of this Ministry shall continue to be adhered by “Symbiosis International”.

SANJAY KUMAR SINHA

Jt. Secy.

---

No. F.9-11/2007-U3(A).—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-11/2007-U3(A) dated 27.02.2008, on the advice of UGC, had declared Yenepoya University, Mangalore, Karnataka consisting of Yenepoya Dental College, Mangalore as “deemed to be University”, with effect from the date on which the aforesaid Dental College disaffiliates itself from its affiliating University viz. Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka, Bangalore.

3. And further whereas, the Hon’ble Supreme Court of India vide its judgment Order dated 03.11.2017 in Civil Appeal Nos. 17869-17870/2017 (arising out of SLP(C) Nos.19807-19808/2012) filed by Orissa Lift Irrigation Corp. Ltd Versus Rabi Sankar Patro & Ors. and Civil Appeal Nos.17902-17905/2017 (arising out of SLP C Nos.35793-96/2012) titled as Vijay Kumar & Ors Vs. Kartar Singh & Ors held that UGC shall take appropriate steps for implementing Section 23 of the UGC Act and restraining Deemed to be Universities from using the word ‘University’ within one month from today.

4. And whereas, Section 23 of the UGC Act, 1956 says “*no institution, whether a corporate body or not, other than a University established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act shall be entitled to have the word “University” associated with its name in any manner whatsoever: Provided that nothing in this section shall, for a period of two years from the commencement of this Act, apply to an institution which, immediately before such commencement, had the word “University” associated with its name*”.

5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, as per direction of Hon’ble Supreme Court and on the advice of the UGC, do hereby change the name of “Yenepoya University” to “Yenepoya” by deleting the word ‘University’ from its name w.e.f. the issuance of this Notification. “Yenepoya” shall not use the word ‘University’ suffixed to its name but may mention the word “deemed to be university” within parenthesis suffixed thereto.

6. All other conditions mentioned in the earlier Notification dated 27.02.2008 shall continue to be adhered by “Yenepoya”.

SANJAY KUMAR SINHA

Jt. Secy.

---

ICR DIVISION

New Delhi, the 19<sup>th</sup> January, 2018

No.F.10-3/2017-U.3(A).—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an institution of higher learning as a deemed-to-be-university.

2. **And whereas**, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-42/2006-U3(A) dated 20.02.2009, on the advice of UGC, had declared ‘Koneru Lakshmaiah Education Foundation’ Vijayawada, Andhra Pradesh as an “Institution Deemed to be University”, for the purposes of the aforesaid Act, **provisionally for a period of five years**, subject to the following conditions:

- i. Koneru Lakshmaiah Education Foundation shall comprise 'Koneru Lakshmaiah College of Engineering', Greenfields, Kunchanapalli Post, Vaddeswaram, Guntur District, Andhra Pradesh, as its constituent teaching unit;
- ii. Koneru Lakshmaiah Education Foundation shall become an 'Institution Deemed to be University' with effect from the date of disaffiliation of Koneru Lakshmaiah College of Engineering from its affiliating University, viz. Acharya Nagarjuna University, Nagarjuna Nagar, Guntur District, Andhra Pradesh;
- iii. The declaration as made above shall cover only those academic courses that are conducted hitherto by the said Koneru Lakshmaiah College of Engineering under affiliation to the Acharya Nagarjuna University and those courses that it may start in future as per the norms of the relevant Statutory Council(s) concerned (such as the AICTE, etc.) and the UGC;
- iv. Koneru Lakshmaiah Education Foundation shall admit students to the approved academic courses / programmes of Koneru Lakshmaiah College of Engineering, under its ambit, only with effect from the next academic year, i.e. 2009-10;
- v. The status of 'Deemed to be University' conferred on Koneru Lakshmaiah Education Foundation shall be reviewed after a period of five years;
- vi. Koneru Lakshmaiah Education Foundation shall maintain the standards and norms as are specified by the All India Council for Technical Education (AICTE) and the UGC from time to time.

3. **And further whereas**, the Central Government vide Notification No. 9-42/2006-U3(A) Vol.2 dated 11<sup>th</sup> July, 2017, on the advice of the UGC, extended/regularized the status of Deemed to be University of 'Koneru Lakshmaiah Education Foundation' Vijayawada, Andhra Pradesh for another period of five years i.e. from 20.02.2014 to 19.02.2019 subject to terms & conditions of this Ministry's Notification No.9-42/2006-U3(A) dated 20.02.2009 and the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016 and its amendments, if any, from time to time. This notification is further subject to following conditions:

- i. Koneru Lakshmaiah Education Foundation shall replace the word 'University' with "Deemed to be University" wherever it is being used and make other necessary amendments, whatever required, as per the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016.
- ii. Koneru Lakshmaiah Education Foundation shall rectify all the deficiencies pointed out and suggestions given by the UGC Expert Committee and shall submit compliance report along with documentary proof to UGC within a period of 6 months.
- iii. Koneru Lakshmaiah Education Foundation shall admit students to the approved academic courses / programmes of Koneru Lakshmaiah College of Engineering, under its ambit or any other Courses which are approved by Statutory Council(s) concerned and UGC, wherever required. It shall not admit students in B. Pharm, BFA and BBA-LLB courses and other such courses without approval of the UGC and Statutory Councils concerned.
- iv. The status of Deemed to be University shall be further extended, on the advice of UGC and also after fulfillment of the above conditions.

4. **And whereas**, Koneru Lakshmaiah Education Foundation, Vijayawada, Guntur District, Andhra Pradesh submitted an application on 19<sup>th</sup> June, 2017 for starting of an Off-Campus Centre at Aziznagar, Moinabad Road, Rangareddy district, Telangana.

5. **And whereas**, UGC examined the application with the help of its Expert Committee as well as Expert Committee of All India Council for Technical Education (AICTE). The reports of the both Committees were placed before the Commission in its 525<sup>th</sup> meeting (Item No.2.01) held on 04.09.2017 in which the following has been resolved:

*"The Commission resolved that the proposal submitted by Koneru Lakshmaiah Education Foundation (Deemed to be University), Vaddeswaram, Guntur District, Andhra Pradesh for starting an Off-Campus Centre at Hyderabad be approved subject to submission of the compliance report as per the suggestions given by UGC/AICTE visiting Committee."*

6. **And further whereas**, the reports of both Committees were examined in the Ministry as per the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016 and certain clarifications / information were sought from the UGC. Accordingly, UGC sent a one member Committee to Koneru Lakshmaiah Education Foundation, Vijayawada, Guntur District, Andhra Pradesh to verify the points raised by the Ministry. The report of one member Committee was placed before the Commission in 527<sup>th</sup> meeting (Item No. 3.01) held on 22.12.2017 wherein the Commission considered the report of the Committee and approved the verification report.

7. **Now, therefore,** in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby permit Koneru Lakshmaiah Education Foundation, Vijayawada, Andhra Pradesh for starting *an Off-Campus Centre at Aziznagar, Moinabad Road, Rangareddy district, Telangana*, with prospective date for the following courses:

- i. Computer Science and Engineering
- ii. Electronics and Communication Engineering
- iii. Electronics and Computer Engineering
- iv. Master of Business Application

8. The declaration as made in Para 7 above is further subject to review of the Campus by UGC biennially for six years and subsequently after five years as prescribed under the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016, as amended from time to time. The said permission is further subject to fulfilment of the conditions mentioned at Sr. No.5 of the endorsement to this Notification;

SANJAY KUMAR SINHA

Jt. Secy.

---

U.3(A) Section

New Delhi, the 7th February, 2018

No. F.9-1/99-U3(A)Vol.2.—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-9/99-U.3 dated 21.08.2001, on the advice of UGC, had declared International Institute of Information Technology, Hyderabad as an Institution deemed to be University”, for the purpose of aforesaid Act with immediate effect *subject to review after five years*.

3. And whereas, UGC reviewed the functioning of the Deemed to be University with the help of its Expert Committee. The report of the Committee was placed before the Commission in its 524<sup>th</sup> meeting held on 24.08.2017 in which following resolution was passed:

*“After having considered the recommendations of the UGC Expert Committee, the Commission approved the proposal. It was also decided to forward it to MHRD for further necessary action. Further, it was decided to direct the Institute to align its MoAs etc. in accordance with UGC Regulations, 2016 within one year.”*

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby extend / regularize deemed to be University status to ‘International Institute of Information Technology’, Hyderabad *from 21.08.2006 onwards* subject to condition that the Institution shall amend its MoA / Rules in accordance with UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016, as amended from time to time.

5. The all other conditions mentioned in the earlier Notification dated 21.08.2001 shall continue to be adhered by “International Institute of Information Technology”, Hyderabad.

SANJAY KUMAR SINHA

Jt. Secy.

---

ICR Division

New Delhi, the 23<sup>rd</sup> February, 2018

No.F.10-12/2016-U.3(A).—**Whereas**, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an institution of higher learning as a deemed-to-be-university.

2. **And whereas**, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-39/2001-U.3 dated 11.01.2003, on the advice of UGC, had declared Dr. D Y Patil Vidyapeeth, Pimpri, Pune comprising Padmashree Dr. D. Y. Patil Medical College, Hospital & Research Centre, Pimpri, Pune as an Institution Deemed to be University subject to the following conditions:

- i. It shall adhere to the guidelines / instructions issued by UGC from time to time as applicable to Deemed Universities.
- ii. The Deemed to be University status is granted only in respect of Padmashree Dr. D. Y. Patil Medical College, Hospital & Research Centre, Pimpri, Pune and the proposal in respect of any other institutions of Dr. D Y Patil Vidyapeeth, Pimpri, Pune is not approved by the Government of India. This position will be clarified by Dr. D Y Patil Vidyapeeth, Pimpri, Pune in all its circular, advertisements, prospectus, etc.

3. **And further whereas**, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide Notification No.9-39/2001-U.3 dated 20.09.2006 brought following three Institutions under the ambit of Dr. D Y Patil Vidyapeeth (Deemed to be University), Pimpri, Pune:

- i. Dr. D. Y. Patil Dental College & Hospital, Pimpri, Pune (Maharashtra);
- ii. Padmashree Dr. D. Y. Patil College of Nursing, Pimpri, Pune (Maharashtra);
- iii. Padmashree Dr. D. Y. Patil College of Physiotherapy, Pimpri, Pune (Maharashtra)

4. **And whereas**, the Deemed to be University submitted an application on 29.03.2017 for inclusion of Dr. D. Y. Patil College of Ayurved and Research Centre, Pimpri, Pune & Dr. D. Y. Patil Homoeopathic Medical College & Research Centre, Pimpri, Pune under the ambit of Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth (Deemed to be University), Pune, Maharashtra. The application was forwarded to UGC for examination in accordance with the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016 and tendering its advice to the Ministry.

5. **And whereas**, UGC examined the application with the help of its Expert Committee consisting of a nominee from Central Council of Indian Medicine and Central Council for Homoeopathy. The report of the UGC Expert Committee was placed before the Commission in its 527<sup>th</sup> meeting (Item No.2.02) held on 22.12.2017 in which following resolution was passed:

*“Considered and approved with the condition, that the suggestions by the visiting Expert Committee, if any, will be addressed within a period of 6 months and the compliance report would be submitted alongwith the documentary proof to UGC.”*

6. **And further whereas**, UGC vide its letter No.30-1/2017 (CPP-I/DU) dated 20<sup>th</sup> January, 2018 has informed the Deemed to be University has complied with the suggestions as pointed out by the UGC visiting Expert Committee.

7. **Now, therefore**, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, hereby accord its approval for inclusion of the following two Institutions under the ambit of Dr. D Y Patil Vidyapeeth (Deemed to be University), Pimpri, Pune as Constituent Institutions of the Deemed to be University with effect from the date of disaffiliation from their affiliating University i.e. Maharashtra University of Health Sciences, Nasik:

- a) Dr. D. Y. Patil College of Ayurved and Research Centre, Pimpri, Pune; and
- b) Dr. D. Y. Patil Homoeopathic Medical College & Research Centre, Pimpri, Pune

8. The said permission is further subject to fulfilment of the conditions mentioned at Sr. No.8 of the endorsement to this Notification;

SANJAY KUMAR SINHA

Jt. Secy.